ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज

सच्ची खबर सबसे पहले

आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

online- jwalaexpress.com

वर्ष - 05, अंक -41 | दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 11 जून से 17 जून (प्रत्येक गुरुवार) | पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

बस्तर में आमदनी दोगुनी करने का बड़ा संकल्प : तीन साल में हर परिवार की आय 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक पहुंचाने का लक्ष्य

बस्तर में दूध, खेतों तक पानी, युवाओं को काम और गांवों को नई पहचान देने की तैयारी

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रखा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में नक्सलवाद से मुक्त बस्तर की नई तस्वीर देश के सामने रखी। उन्होंने कहा कि दशकों तक हिंसा की मार झेलने वाला बस्तर अब आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि आधारित विकास का मॉडल बनेगा।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बस्तर के आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, दुग्ध क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, पर्यटन को बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने तथा एआई और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर अब नई पहचान की ओर बढ़ रहा है। वहां दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेतों तक पानी पहुंचाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, गांवों में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में बस्तर के परिवारों की मासिक आय बढ़ाकर 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में बस्तर के लगभग 85 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। सरकार खेती, पशुपालन, वन उपज, छोटे उद्योग और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में डेयरी मॉडल को तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके तहत आदिवासी परिवारों को दुधारू गाय और भैंस उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य गांवों में स्थायी आय का स्त्रोत तैयार करना है। इस पहल से महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा गांवों में डेयरी केंद्र, दूध संग्रहण, परिवहन और स्थानीय बाजार जैसी नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं से 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इंद्रावती नदी क्षेत्र में सालभर पानी उपलब्ध होने से खेती बेहतर होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान धान के साथ-साथ सब्जियां, फल तथा अन्य नकदी फसलें भी उगा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 36 लाख लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार की जा रही है। इससे मरीजों के इलाज, बीमारी और दवाओं का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा तथा डॉक्टरों को समय पर सही जानकारी मिल सकेगी। इसका सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगा।

उन्होंने बताया कि बस्तर में बने लगभग 200 सुरक्षा शिविरों को अब सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को राशन, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की 371 योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर में बने लगभग 200 सुरक्षा शिविरों को अब सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को राशन, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बैंकिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की 371 योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चित्रकोट और बौद्ध धर्म से जुड़े तीर्थस्थल सिरपुर को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। बस्तर में वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है, जबकि सिरपुर में ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, संग्रहालय और महानदी तट के विकास पर कार्य जारी है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है। पर्यटकों के आने से होटल, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प, दुकानदारों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मिलता है।

समाचार सार

बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने बढ़ाई लोन की ब्याज दरें

नईदिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स में 5 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। लोन की ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी कुछ चुनिंदा अवधि वाले लोन के लिए ही की गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने बताया कि नई ब्याज दरें शुक्रवार, 12 जून से लागू होंगी। यानी, 12 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक के एमसीएलआर से जुड़े लोन महंगे हो जाएंगे।

मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

नईदिल्ली। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। हालांकि, आईटी स्टॉक्स में आज एक बार फिर बड़ा नुकसान देखने को मिला। आज बीएसई सेंसेक्स 150.63 अंकों (0.20%) की गिरावट के साथ 73,832.55 अंकों पर बंद हुआ। जबकि, एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स आज 53.35 अंकों (0.23 प्रतिशत) के नुकसान के साथ 23,161.60 अंकों पर बंद हुआ।

भारत बना ग्लोबल फाइनेंशियल टैलेंट हब

नईदिल्ली। भारत वैश्विक वित्तीय सेवा उद्योग के लिए तेजी से एक प्रमुख टैलेंट हब के रूप में उभर रहा है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी कॉलियर्स की 'ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज़ मार्केट्स- टॉप टैलेंट लोकेशन्स 2026नामक रिपोर्ट में यह पाया गया कि वित्तीय सेवाओं की लोकेशन रणनीतियां बदल रही हैं क्योंकि कंपनियां टैलेंट तक पहुंच, लागत प्रतिस्पर्धा और तेजी से बदलती तकनीक के बीच संतुलन बना रही हैं।

पलक झपकते भारत से नेपाल और नेपाल से भारत पहुंचेगा पैसा

नईदिल्ली। भारत और नेपाल ने मिलकर क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए यूपीआई आधारित मनी ट्रांसफर सिस्टम लॉन्च कर दिया है। दोनों देशों ने बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों, कारोबारियों और यात्रियों के लिए पेमेंट और मनी ट्रांसफर को आसान बनाने के उद्देश्य से 6 जून को पी2पी(दो इकाइयों के बीच) क्रॉस-बॉर्डर धन प्रेषण व्यवस्था शुरू की है।

बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने बढ़ाई लोन की ब्याज दरें

नईदिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स में 5 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। लोन की ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी कुछ चुनिंदा अवधि वाले लोन के लिए ही की गई हैं।

टीएमसी में बगावत, बगावती खेमे में शामिल हो सकते हैं और सांसद

अभी भी संपर्क में हैं 20 सांसद, बढ़ सकता है आंकड़ा: काकोली घोष

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी हालात पूरी तरह बेकाबू नजर आ रहे हैं। पार्टी के भीतर की रार अब खुलकर सड़कों और मीडिया के सामने आ चुकी है। इस बीच लोकसभा सांसद काकोली घोष के ताजा बयानों ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। टीएमसी सांसद ने साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
लोकसभा सांसद काकोली घोष ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक बगावती खेमा होने की बात को हवा दे दी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या टीएमसी के 20 सांसद बागी गुट में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया। काकोली घोष ने सीधे तौर पर कहा कि अभी तक बागी खेमे में 20 सांसद शामिल हैं। लेकिन यह संख्या यहीं रुकने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि कई बड़े नेता और सांसद लगातार उनके संपर्क में हैं। इस बयान के बाद टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व में हड़कंप मच गया है।

आरजी कर मामले पर भावुक

आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर कल्याण बनर्जी ने काकोली घोष पर निशाना साधा था। इस पर पलटवार करते हुए काकोली घोष काफी भावुक और हमलावर नजर आईं। उन्होंने कल्याण बनर्जी को अतीत की याद दिलाई। काकोली ने कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस रात इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस वक्त उनका पूरा परिवार सड़कों पर उतरा हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन वाली रात उनकी बेटी और बेटा दोनों जनता के साथ सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान उनके छोटे बेटे पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। काकोली घोष ने कहा कि उन्होंने इस पूरी घटना और जमीनी हकीकत को लेकर ममता बनर्जी से खुद सीधे बात की है।

ममता और टीएमसी के साथ खड़ा रहना मेरा फर्ज : शत्रुघ्न सिन्हा

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में फूट की चर्चाओं के बीच पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वह ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी और पार्टी का साथ देना उनका कर्तव्य है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सबसे पहले आसनसोल और पश्चिम बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और समर्थन दिया है। उन्होंने बताया कि वह ममता बनर्जी के बुलावे और उनके निर्देश पर ही आसनसोल आए थे। उन्होंने वहां पहली बार उपचुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरी बार भी वह बड़े अंतर से चुनाव जीते। सिन्हा ने कहा कि वह बंगाल के सभी लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों।

एनआईटी रायपुर और जीएमडीसी के बीच एमओयू

भूविज्ञान और क्रिटिकल मिनरल्स अनुसंधान को मिलेगी नई दिशा

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जीएमडीसी) के अंतर्गत कार्यरत अग्रणी अनुसंधान एवं परामर्श संस्था गुजरात मिनरल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी सोसायटी (जीएमआरआईसीएस) के बीच बुधवार को भूविज्ञान, खनन एवं क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

यह समझौता शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को नई गति देने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। समझौता ज्ञापन पर एनआईटी रायपुर के निदेशक प्रो. एन. वी. रमना राव तथा

जीएमआरआईसीएस/जीएमडीसी, अहमदाबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. के. सिन्हा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जीएमडीसी के सीनियर जनरल मैनेजर (टेक) श्री ए. के. माकडिया, जनरल मैनेजर (एचआर) श्री एस. डी. दाव, एनआईटी रायपुर के डॉ. नीरज विश्वकर्मा, डॉ. डी. सी. झरिया सहित संस्थान के संकाय सदस्य उपस्थित रहे। यह समझौता प्रारंभिक रूप से पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे दोनों संस्थानों की सहमति से आगे भी विस्तारित किया जा सकेगा।

पश्चिम एशिया संकट: अमेरिका-ईरान में आर-पार

ट्रंप बोले-ईरान पर होगा भीषण हमला, तेल पर करेंगे पूर्ण नियंत्रण

अमेरिका-ईरान टकराव के बीच खाड़ी देशों पर भी हमले, कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा जवाब

नई दिल्ली (ए)। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन जोरदार हमले हुए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत जल्द अमेरिका ईरान के तेल और गैस उद्योग पर अपना पूरा कब्जा जमा लेगा। इसमें ईरान का सबसे मुख्य तेल केंद्र खर्ग द्वीप भी शामिल है।

अमेरिका का हमला हुआ तेज, ईरान का भी पलटवार

दोनों देशों के बीच यह भीषण लड़ाई गुरुवार सुबह तक चलती रही। अमेरिकी सेना का यह हमला पिछले दिन के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा, तेज और आक्रामक था। इस हमले से ईरान को काफी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ, ईरान ने अपने नुकसान की पूरी जानकारी तो नहीं दी है। लेकिन कहा कि उसने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने ठीक एक दिन पहले भी इन देशों पर हमला किया था।

ओमान के निकट अमेरिकी मिसाइल हमले में हमीरपुर के आदित्य शर्मा की मौत

शिमला (ए)। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के लिए एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। ओमान तट के निकट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास हुए जहाज हमले में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के युवा नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई है। आदित्य हमीरपुर के गलोड़ क्षेत्र के निवासी थे और पालाउ ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर डेक कैडेट के रूप में कार्यरत थे। उनकी मौत की पुष्टि होने के बाद परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। हड़ेटा पंचायत के भालू गांव निवासी आदित्य जहाज पर डेक कैडेट के रूप में तैनात थे। बीते वर्ष नंवबर माह में वह घर से ड्यूटी के लिए गए थे। आदित्य के पिता राजेश कुमार जालंधर में निजी कंपनी में कार्यरत हैं जबकि माता गृहिणी हैं। आदित्य अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, हादसे की सूचना के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है।

समुद्र में सख्त नाकेबंदी, तेल टैंकर को उड़ाया

अमेरिकी सेना ने ईरान के सभी बंदरगाहों को चारों तरफ से घेर रखा है। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को बताया कि उनकी समुद्री नाकेबंदी पूरी मजबूती से जारी है। इसी नाकेबंदी के दौरान अमेरिकी सेना ने समुद्र में एक बड़े तेल टैंकर पर मिसाइल मार दी। यह टैंकर चोरी-छिपे ईरान का तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था। मिसाइल लगने के बाद यह तेल टैंकर पूरी तरह बर्बाद और बेकार हो गया है। ट्रंप के इस नए बयान के बाद अब पूरे इलाके में युद्ध की दहशत फैल गई है।

राम मंदिर चंदा गबन मामला

सीसीटीवी फुटेज और कैश हैंडलिंग प्रक्रिया की पड़ताल में जुटा ट्रस्ट, फूटे विरोध के स्वर

अयोध्या (ए)। राम मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी और गबन के आरोपों को लेकर चर्चा लगातार तेज है, लेकिन इस पूरे मामले पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के शीर्ष ट्रस्टी अब तक सार्वजनिक रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट स्तर पर मामले की गोपनीय जांच कराई जा रही है और जांच पूरी होने तक कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी खुलकर कुछ कहने से बच रहा है।

जानकारी के मुताबिक, जांच का केंद्र केवल कथित गबन तक सीमित नहीं है, बल्कि दान संग्रह से लेकर उसकी गणना, रिकॉर्डिंग और बैंक में जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया की तकनीकी समीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि संबंधित तिथियों की सीसीटीवी फुटेज, दान पात्रों को खोलने की प्रक्रिया, कैश काउंटिंग के दौरान मौजूद कर्मचारियों की भूमिका और डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान कराया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मंदिर में दान राशि की गणना बहुस्तरीय व्यवस्था के तहत होती है। दान पात्रों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खोला जाता है और

गणना के दौरान कई स्तरों पर निगरानी रखी जाती है। ऐसे में जांचकर्ता यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कथित गड़बड़ी प्रक्रिया संबंधी कमी है या फिर किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका सामने आती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ कर्मचारियों के दायित्वों में बदलाव और संदिग्ध गतिविधियों की आंतरिक समीक्षा भी किए जाने की चर्चा है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बीच संत समाज और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई प्रमुख लोगों की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग उठाए जाने के बाद मामले को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। राम मंदिर की दान राशि में कथित गबन और चोरी के आरोपों का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। कटियार के बयान के बाद यह मुद्दा और चर्चा में आ गया है। वहीं संत समाज के कई प्रमुख संतों ने भी पारदर्शी जांच कर सच्चाई सामने लाने की बात कही है।

जांच से ही स्पष्ट होगी पूरे मामले की वास्तविक स्थिति: विवेक

रामनगरी की प्राचीन पीठ दंतधावन कुंड आचारी मंदिर के पीठाधिपति महंत विवेक आचारी ने भी कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़े इस विषय में जो भी तथ्य हैं, उन्हें जनता के सामने लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपों से राम मंदिर ट्रस्ट व अयोध्या की छवि धूमिल हो रही है। जांच से ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और श्रद्धालुओं के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सकेगा।

एमपी-गुजरात की सभी राज्यसभा सीटों पर भाजपा जीती, राजस्थान में बीजेपी को दो, कांग्रेस को एक सीट

एमपी की तीन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को आज ही जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। दरअसल, नाम वापसी की समय-सीमा खत्म होने के बाद और केवल तीन पदों के लिए तीन ही नामांकन शेष रहने के चलते सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए आज 11 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की अंतिम समय-सीमा तय है। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद स्थिति यह बन गई कि तीन सीटों के मुकाबले केवल तीन ही उम्मीदवार मैदान में रह गए, जिससे चुनाव निर्विरोध हो गया। जिसके बाद बीजेपी के तीनों राज्यसभा सांसदों का स्वागत पार्टी कार्यालय में करने की भी तैयारी की जा रही है।
विधायक दल के बाद ये सभी नव-निर्वाचित सांसद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे।

राजस्थान की तीनों सीट पर पूनिया अलका और डांगी निर्विरोध निर्वाचित

जयपुर। राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी हो गई है। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद बीजेपी के डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका गुर्जर तथा कांग्रेस के नीरज डांगी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। तीनों सीटों के लिए केवल तीन उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया था। नाम वापसी के अंतिम दिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद राज्य

निर्वाचन आयुक्त नवीन जैन ने तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा भेजा है लेकिन सियासी जानकार कहते हैं कि इसके पीछे का असल मकसद विधानसभा चुनाव हैं।

गुजरात के चारों सीटों पर निर्विरोध जीते भाजपा उम्मीदवार

मौजूदा गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 161 है। कांग्रेस की 12 और आम आदमी पार्टी की केवल पांच सीटें हैं। इसलिए किसी भी विपक्षी दल ने उम्मीदवार नहीं उतारा। इसी वजह से निर्वाचन आयोग ने गुजरात में भाजपा के चारों उम्मीदवारों को निर्विरोध घोषित कर दिया है।
मुकेश राठवा- छोटा उदयपुर जिले के क्वांट से ताल्लुक रखते हैं। यह एक जनजातीय क्षेत्र है।
जितेंद्र कंजारिया- सतवाड़ा समाज से आते हैं। देवभूमि द्वारका जिले के एक प्रमुख भाजपा नेता और कार्यकर्ता हैं।

मानसिंह परमार- राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो वर्तमान में गुजरात प्रदेश भाजपा बख्शी पंच मोर्चा के अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं।
राजू शुक्ला- ब्राह्मण समुदाय से हैं। कड़ी-कलोल इलाके के रहने वाले हैं।

तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा के द्वारा प्रांतीय निकाय के आव्हान पर महंगाई भत्ता सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा को भोजन अवकाश के दौरान ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, रायपुर के निर्णय एवं समस्त सहयोगी संघों की सहमति के अनुसार, 'मोदी की गारंटी' के तहत कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं को लागू कराने हेतु भोजन अवकाश के दौरा 6 बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण ज्ञापन प्रस्तुत किया। राज्य के लगभग 4.50 लाख अधिकारी-कर्मचारी 01 जनवरी 2026 से केंद्र द्वारा स्वीकृत 2% डीए से वंचित हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी निर्धारित तिथि से महंगाई भत्ता/राहत दी जाए तथा डीए एरियर की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए। विधानसभा बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा घोषित कैशलेस मेडिकल सुविधा के नियम तत्काल जारी किए जाएं। केंद्र एवं मध्य प्रदेश की भांति सेवानिवृत्ति पर 240 दिन की जगह 300 दिन का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जाए। संविदा, दैनिक वेतन भोगी एवं अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित कर मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुनिश्चित की जाए। एलबी कैडर के सभी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर लाभ दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति पर 10% की सीलिंग समाप्त कर सभी रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ज्ञापन के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बलौदाबाजार भाटापारा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार दुबे छत्तीसगढ़ अधिकारी/कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष पी के हिरवानी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, के जिला संयोजक डाक्टर एल.एस. ध्रुव स्वास्थ्य संयोजक संघ के अध्यक्ष विजय साहू, डिगेंद्र वर्मा, रिपू सुदन साहू, सत्यनारायण साहू अनियमित कर्मचारी संघ कोमल पडवार, पंकज वैष्णव, मुकेश वर्मा, कर्मचारीचारी कांग्रेस जिलाअध्यक्ष संतोष साहू, कृष्णा घृतलहरे, मनोज पैकरा, गीता साहू, संतोष सतनामी, नरेन्द्र देवांगन, यशवंत वर्मा, प्रेमप्रकाश केशरवानी, अगनू राम ध्रुव, राजेश नेताम, अमृतलाल मनहर उमेश धीवर, राजेश अग्रवाल, चोवाराम ध्रुव, जय कुमार यादव, अहिल्या साहू, डिम्पल चंद्राकर, निरा महंत, कृष्णा कुमारी यादव, रम्भा यादव, देवकी देवदास, नीलावती ध्रुव, दुर्गेश यादव, फिरोज खान, सोनचंद साहू, एवं अलग अलग सहयोगी संगठनो पदाधिकारी एवं सदस्यसाथीगण उपस्थित रहे।

जिला पंचायत सीईओ चंद्राकर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना, लक्ष्य अनुरूप प्रगति एवं आगामी रणनीतियों पर चर्चा के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर की अध्यक्षता में जिला पंचायत गरियाबंद के सभाकक्ष में एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के समस्त विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक, आईएफसी एंकर, क्षेत्रीय समन्वयक, पीआरपी, वरिष्ठ सीआरपी, एफ्पीओ एवं एफ्पीसी-सीईओ सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ चंद्राकर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विकासखण्डों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईएफसी की प्रगति एवं नवीन प्रस्ताव, लखपति दीदी एवं लखपति ग्राम की प्रगति, 10 के एफपीओ एवं एफ्पीसी की स्थिति, प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन एवं संचालन, एसवीईपी एवं ओएसएफ गतिविधियां, फार्म एवं नॉन-फार्म आजीविका, एसआईएसडी लक्ष्य, समूह सैचुरेशन, सीएलएफ ट्रांजेक्शन एंट्री, मॉडल सीएलएफ एमपीआर प्रविष्टि, बैंक लिंकेज, एंटरप्राइज फाइनेंस तथा एनपीए की स्थिति सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। चंद्राकर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हुए आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए।

उपार्जन केंद्र ढोर्रा और सीनापली में धान के रख-रखाव में बड़ी अनियमितता

गरियाबंद। जिले के धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी कार्य के दौरान बड़ी अनियमितता सामने आई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धान उपार्जन कार्यों की समीक्षा एवं जांच में उपार्जन केंद्र ढोर्रा और सीनापली में भारी मात्रा में धान की कमी (शॉर्टेज) पाई गई है। जांच के दौरान पाया गया कि दोनों उपार्जन केंद्रों में निर्धारित मात्रा के अनुसार धान उपलब्ध नहीं है। जिससे समिति को आर्थिक क्षति हुई है। भौतिक सत्यापन के अनुसार उपार्जन केंद्र ढोर्रा में कुल 83 हजार 449.60 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई थी। जबकि जांच के दौरान 2 हजार 113.24 क्विंटल धान कम पाया गया। इससे समिति को 65 लाख 51 हजार 44 रुपये की वित्तीय हानि हुई है। इसी प्रकार सीनापली उपार्जन केंद्र में कुल 87 हजार 26 क्विंटल धान खरीदी दर्ज की गई है। जबकि 2 हजार 151.96 क्विंटल धान की कमी पाई गई। जिससे समिति को 66 लाख 71 हजार 76 रुपये का नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि नियमानुसार धान उपार्जन में सुखत (ड्रायेज) मान्य नहीं है। इसके बावजूद दोनों केंद्रों में इतनी बड़ी मात्रा में धान की कमी पाया जाना गंभीर अनियमितता की ओर संकेत करता है। कलेक्टर श्री बीएस उइके के निर्देश पर सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त सुश्री महेश्वरी तिवारी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए धान की कमी के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई किए जाने के लिए शाखा प्रबंधक गोहरापदर को निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि धान उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या वित्तीय क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

बीज उत्पादन प्रक्रिया शीघ्र होगी प्रारम्भ किसानो को मिलेगा अधिक आय के साधन

बलौदाबाजार। जिले के किसानों को खाद -बीज की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही उनके आय बढ़ाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा पहल की जा रही है। इसी कड़ी में जिले में बीज़ उत्पादन की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड छेरकापुर एवं कृषि विभाग के समन्वय से किसानों को बीज उत्पादन कार्यक्रम पंजीयन की कार्यवाही की जएगी । बीज उत्पादन हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा बी-1 की छायाप्रति के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर किसान पंजीयन करा सकते हैं। बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीयन 930 रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। अपने खेत की फसल का बीज प्रमाणीकरण हेतु बीज प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं निगम छेरकापुर पलारी कार्यालय कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क कर निर्धारित समय सीमा में पंजीयन अवश्य करा सकते हैं। बीज़ परीक्षण में मानक प्राप्ति उपरान्त कृषकों को 3850 रूपये प्रति क्विंटल की दर से राशि भुगतान किया जाएगा जो कि सामान्य दर 3100 से 750 रूपये अधिक है। जिससे किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। उप संचालक कृषि दीपक नायक ने बताया कि खरीफ वर्ष 2026 में जिले में बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु 1250 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।आगामी वर्ष 2027 हेतु बीज मांग को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक किसानों को बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2025 में 416 कृषकों द्वारा 746.350 हेक्टेयर में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया था। किसानों को खरीफ मौसम वर्ष 2026 हेतु उच्च गुणवत्ता वाले आधार एवं प्रमाणित बीज समय पर उपलब्ध कराने की व्यापक व्यवस्था की गई है। कृषकों को धान, लघु धान्य (कोदो-कुटकी), अरहर, उड़द, मूंग, तिल, सोयाबीन, सनई ढेंचा एवं अन्य प्रमुख खरीफ फसलों के आधार एवं प्रमाणित बीजों का वितरण सहकारी समितियों, कृषि विभाग के कार्यालयों, बीज प्रक्रिया केन्द्र, छेरकापुर (पलारी) के माध्यम से किया जा रहा है। जिले की कुल बीज मांग 32994 क्विंटल के विरूद्ध 19951.40 क्विंटल बीजों का भण्डारण किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध कुल 15073.50 क्विंटल बीजों का कृषकों को वितरण किया चुका है।

भीषण गर्मी में मा कामाख्या ट्रस्ट बना सहारा लोगों को बांट रहा लस्सी छाछ और नाश्ता, राहगीरों को मिल रही राहत

धमतरी। भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच धमतरी में मानव सेवा की एक सराहनीय मिसाल देखने को मिल रही है। दुलारी नगर गली नंबर 3 स्थित मा कामाख्या ट्रस्ट द्वारा पिछले एक माह से लोगों के लिए निशुल्क लस्सी छाछ शरबत भेल चना और समोसे का वितरण किया जा रहा है। गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह पहल लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। ट्रस्ट के सदस्य प्रतिदिन शाम 6 बजे से सेवा कार्य शुरू करते हैं जो सामग्री वितरण समाप्त होने तक जारी रहता है। ट्रस्ट का कहना है कि पूरे गर्मी सीजन में यह सेवा निरंतर जारी रहेगी भीषण गर्मी और लू के बीच राहगीरों मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को ठंडे पेय और नाश्ता उपलब्ध कराना निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कार्य है।

इस सेवा का लाभ लेने वाले लोग ट्रस्ट की जमकर सराहना कर रहे हैं और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बता रहे है। मां कामाख्या ट्रस्ट द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को लस्सी छाछ शरबत भेल चना और समोसे का वितरण किया जा रहा है। गर्मी से परेशान लोगों को इससे काफी राहत मिल रही है। ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि मानव सेवा ही उनका मुख्य उददेश्य है और आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्य जारी रहेंगे।

भीषण गर्मी के इस दौर में मा कामाख्या ट्रस्ट की यह पहल न केवल लोगों को राहत पहुंचा रही है, बल्कि समाज में सेवा और सहयोग का संदेश भी दे रही है। स्थानीय लोगों ने ट्रस्ट के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए ऐसे कार्यों को आगे भी जारी रखने की मांग की है।

पेंशनर्स एसोसिएशन की हुई मासिक बैठक

बलौदाबाजार। पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील इकाई बलौदाबाजार की मासिक बैठक अध्यक्ष एस डी पड़वार के नेतृत्व मे,प्रदेश महामंत्री डी पी जैन, जिलाध्यक्ष एस एम पाध्ये के निर्देशन मे व वरिष्ठ सदस्य पूर्व प्राचार्य जय नारायण केसरवानी की अध्यक्षता मे बुधवार 10 जून को आदर्श प्राथमिक शाला के सभागार मे संपन्न हुई. कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से हुआ .विगत दिनों प्रदेश मुख्यालय रायपुर मे आयोजित प्रांतीय बैठक मे हुई चर्चा व लिए गए निर्णयों से संघ के सदस्यों को अवगत कराते हुए संघ की आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई. इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित छ ग ग्रामीण बैंक शाखा बलौदाबाजार के प्रबंधक राहुल कुमार तथा बैंक के बलौदाबाजारद्य स्थित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख श्री गुप्ता ने पेंशनरों के हित मे बैंक की योजनाओं को विस्तार से बताते हुए उनकी बैंक शाखा मे पेंशन खाता खोलने प्रेरित किया व इसके तुलनात्मक लाभ बताये. अपने उदबोधन मे अध्यक्षता कर रहे डॉ जयनारायण केशरवानी ने कहा कि नियमित बैठकों का उद्देश्य अपने साथियों की कुशल क्षेम जानना होता है. आगामी कार्यक्रमों की रुपरेखा तय होती है. किसी भी पेंशनर की समस्या का समाधान सम्मिलित रूप से हल किया जाता है. उन्होंने सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की तथा सदस्यों से बैठकों मे अधिक से अधिक संख्या मे उपस्थित रहने का आह्वान किया. प्रांतीय महामंत्री डी पी जैन ने सदस्यों द्वारा संघ के लिए दिए गए योगदान को रेखांकित करते हुए सभी से अपनी क्षमता, स्वेच्छा व श्रद्धा से सहयोग कर आगामी जिला सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए आह्वान किया. एस डी पड़वार ने सभी सदस्यों से प्राप्त सहयोग राशि का विवरण प्रस्तुत किया जो उन्हें वार्ड प्रभारियों से प्राप्त हुआ है.बैठक मे डॉ राजेश मिश्रा, सत्यप्रकाश पाण्डेय, डी आर चतुर्वेदी, प्रीत राम धीवर, राजेंद्र मिश्रा, के के वर्मा, यशवंत दुबे, जी पी वर्मा, काशीराम साहू, नेहरू लाल यादव व दौआराम वर्मा उपस्थित थे. वरिष्ठ सदस्य एस पी पाण्डेय ने सभी के प्रति आभार प्रदर्शित किया।

मरादेव में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर दो एकड़ जमीन हुई कब्जामुक्त

धमतरी। जिले के मरादेव क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है करीब दो एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया प्रशासन का कहना है कि नोटिस और अल्टीमेटम देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। दरअसल धमतरी जिले के मरादेव में प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए करीब दो एकड़ भूमि को कब्जामुक्त कराया। बताया जा रहा है कि पांच परिवारों द्वारा जमीन पर दीवार खड़ी कर अतिक्रमण किया गया था। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार नारद ध्रुव नामक व्यक्ति द्वारा बड़े छोटे जंगल की जमीन पर कब्जा कर दीवार बनाई गई थी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मिलावटी शराब के विरुद्ध प्रशासन बड़ी कार्यवाही, 36 हजार रुपए का अवैध शराब जब्त

बलौदाबाजार। जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को आबकारी विभाग द्वारा 36 हजार रुपए के अवैध शराब जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वृत्त पलारी में आबकारी विभाग की संयुक्त दल द्वारा आरोपी (1) मुरली टंडन पिता चंद्रहास (2) नेतराम डहरिया पिता तोरण एवं एक अन्य के रिहायशी मकान से 360 पाव कुल 64.8 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला, खाली शीशी 52 नग, ढक्कन 52 नग एवं एक प्लास्टिक जरीकेन में 15 लीटर रंगीन पानी जप्त किया गया। देशी मदिरा मसाला का बाजार मूल्य 36,000 होना पाया गया। आरोपी (1) मुरली टंडन पिता चंद्रहास (2) नेतराम डहरिया पिता तोरण एवं एक अन्य सा. इंदोरी थाना पिपरीया जिला कबीरधाम के विरूद्ध छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2), 36, 38 (क) 59 (क) का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम, पी. माधव राव, विनोद बांधे आबकारी आरक्षक कोमल निषाद, अभिषेक राठौर, नगर सैनिक दुर्गेश्वरी कुर्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कथित गौमांस बरामदगी पर बवाल हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा

रिहायशी इलाके में बोरियों में मांस मिलने से मचा हडकम्प

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत साल्हेवार पारा के गाढ़ा पारा में उस समय हड़कंप मच गया जब इलाके में बड़ी मात्रा में कथित गौमांस मिलने की सूचना सामने आई घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है, बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोगो को पिछले करीब दो माह से इलाके में कथित रूप से बीफ की बिक्री और उपयोग की शिकायतें मिल रही थीं शिकायतों के आधार पर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जांच की जहां लगभग 50 से 60 किलो संदिग्ध मांस बरामद होने का दावा किया गया इसके साथ ही तालाब किनारे पशु की खाल और अवशेष भी मिले जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया..घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है इस बीच आरोप लगाया जा रहा है कि वार्ड का एक व्यक्ति इस अवैध गतिविधि में शामिल था हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है। हिंदू संगठनों ने मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है।

बरारी में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण शिकायत के बाद निर्माण कार्य पर रोक

धमतरी। धमतरी जिले के ग्राम बरारी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और निर्माण कार्य का मामला सामने आया है शिकायत के बाद कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रुकवा दिया है आरोप है कि करीब 70 डिसमिल सरकारी जमीन पर पेड़ों की कटाई कर रिजॉर्ट निर्माण की तैयारी की जा रही थी वहीं संबंधित व्यक्ति का कहना है कि वह पिछले 40 वर्षों से इस जमीन पर काबिज है और डुबान प्रभावित होने के कारण यहां रह रहा है। फिलहाल प्रशासन ने निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। दरअसल ग्राम बरारी में सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य और पेड़ों की कटाई की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर काम तत्काल रोक दिया गया। वहीं आरोपों के घेरे में आए बरारी निवासी खूबलाल ध्रुव ने कहा कि वह पिछले करीब 40 वर्षों से इस भूमि पर काबिज है और डुबान प्रभावित होने के कारण यहां निवास कर रहा है। उसका कहना है कि कुछ लोगों की शिकायत के चलते यह मामला सामने आया है और प्रशासन जो भी वैधानिक कार्रवाई करेगा वह स्वीकार्य होगी। हालांकि इस पूरे मामले में सवाल यह उठ रहा है कि यदि जमीन शासकीय है तो उस पर निर्माण कार्य किस आधार पर किया जा रहा था और पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है और प्रशासन जांच में जुटा हुआ है।

डौंडी विकासखंड के ग्राम ढोर्रीठेमा निवासी और असम राइफल्स के जवान भोजराम साहू को सैन्य सम्मान 'शौर्य चक्र' से नवाजा गया

दल्लीराजहरा। जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम ढोर्रीठेमा निवासी और असम राइफल्स के जवान भोजराम साहू को उनकी अदम्य वीरता और कर्तव्यपरायणता के लिए देश के प्रतिष्ठित नागरिक सैन्य सम्मान 'शौर्य चक्र' से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में 08 जून को आयोजित गरिमामय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने जिले के वीर जवान भोजराम साहू की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर सराहना व्यक्त की है। कलेक्टर मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जवान भोजराम साहू की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें और उनके परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि वीर जवान भोजराम साहू के द्वारा वर्ष 2025 में मणिपुर के टेंगनौपाल क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान मातृभूमि की रक्षा के लिए जो अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया है वह वास्तव में काबिले-तारीफ एवं अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि साहू द्वारा मातृभूमि की रक्षा के लिए एवं कर्तव्य परायणता के अतुलनीय कार्यों के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रतिष्ठित शौर्य चक्र से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उसके इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से संपूर्ण जिला गौरवान्वित हुआ है। कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने कहा कि जवान भोजराम ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, बल्कि युवाओं के लिए देशभक्ति और प्रेरणा की एक मिसाल पेश की है।

उल्लेखनीय है कि असम राइफल्स के जवान भोजराम साहू को यह सम्मान वर्ष 2025 में मणिपुर के टेंगनौपाल क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में दिखाए गए अदम्य साहस के लिए मिला है। अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर घात लगाकर अचानक हमला कर दिया था। ऐसी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच भोजराम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। उन्होंने बेहद नजदीक से आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान उन्हें एक गोली भी लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद वे पीछे नहीं हटे और अपनी जिम्मेदारी पर डटे रहे। उनके इस अदम्य साहस ने अभियान को सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। बालोद जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर देश के राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र हासिल करने वाले भोजराम साहू की इस सफलता से पूरे जिले और छत्तीसगढ़ राज्य में हर्ष का माहौल है।

सुशासन तिहार का समापन, विधायक दीपेश साहू ने सुनीं जनसमस्याएं और हितग्राहियों को किया लाभान्वित

जनसमस्या निवारण शिविर में उमड़ा जनविश्वास, शासन की योजनाओं का मिला सीधा लाभ

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन, पारदर्शिता एवं जनकल्याण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित सुशासन तिहार 2026 का समापन आज विकासखंड बेरला के ग्राम पंचायत रेवे में आयोजित विशाल जनसमस्या निवारण शिविर के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता कर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी समस्याओं एवं मांगों से प्रशासन को अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक दीपेश साहू ने नागरिकों की समस्याएं एवं मांगें गंभीरता से सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित कर प्रमाण-पत्र एवं स्वीकृति पत्र प्रदान किए।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा शासन का लाभ : विधायक दीपेश साहू

शिविर को संबोधित करते हुए विधायक दीपेश साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए आम नागरिकों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविरों के माध्यम से शासन एवं प्रशासन स्वयं गांव-गांव पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्क र लगाने से राहत मिल रही है तथा समयबद्ध तरीके से उनकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित हो रहा है।

हितग्राहियों को मिला विभिन्न योजनाओं का लाभ

शिविर के दौरान पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, श्रम एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। विधायक साहू ने नागरिकों से शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया तथा कहा कि जनभागीदारी से ही विकास की प्र या को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, उपलब्ध सेवाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को दी। साथ ही प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्यवाही भी की गई। उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जिले में नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं शासन की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 15 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 23, कुल 41 जनसमस्या निवारण शिविरों का सफल आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत रेवे में आयोजित अंतिम शिविर के साथ जिले में सुशासन तिहार का सफल एवं प्रभावी समापन हुआ। इस अवसर पर रजककार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, कलेक्टर सुप्रतिष्ठा ममगाईं, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दीप्ति वर्मा, पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल, जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी, जिला पंचायत सभापति प्रीतम चंदेल, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि राजेंद्र शर्मा, बलराम पटेल, सरपंच रघुवीर (पिंटू) सिन्हा, उपसरपंच केदार सिन्हा, दिलीप निषाद, अमृत महेश्वरी, डोमेन्द्र राजपूत, मनहरण साहू, मोहन साहू, थानेश्वर साहू, जगदीश कुर्रे, एन. प्रकाश साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन जनकल्याण, सुशासन और जनसेवा के संकल्प के साथ हुआ, जिसमें नागरिकों ने शासन की जनहितैषी पहल के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।

विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा अवश्य देने की हिदायत

वर्षा जल संचयन व सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के निर्देश

डोंगरगांव नगर। जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के निर्देशानुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय डोंगरगांव में बुधवार को नए शिक्षा सत्र 2026-27 की तैयारियों को लेकर विकासखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक दो पालियों में सम्पन्न हुई, जिसमें प्रथम पाली में प्राचार्य, संकुल समन्वयक एवं माध्यमिक प्रधान पाठक तथा द्वितीय पाली में प्राथमिक प्रधान पाठकों ने भाग लिया। बैठक में विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयंत साहू ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आगामी 16 जून से विद्यालयों में नियमित अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए सभी संस्था प्रमुखों को समय-सारिणी निर्माण, विद्यालयों की साफ-सफाई, कक्षावार व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक तैयारियां 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रवेश उत्सव, पाठ्यपुस्तक, साइकिल एवं गणवेश वितरण कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किए जाएं। जल एवं विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालयों में वर्षा जल संचयन तथा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। बैठक में जर्जर विद्यालय भवनों की जानकारी संकलित करने, वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, डीटीएच स्मार्ट क्लास के नियमित संचालन, पॉक्सो बॉक्स की सक्रियता, छात्रवृत्ति, आधार अपडेशन, एमबीयू, दैनिक डायरी एवं विभिन्न शैक्षणिक अभिलेखों के संधारण पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव प्रवास बघेल, सेजेस राजनांदगांव के प्राचार्य अमित भोज एवं एडीबीओ सिन्हा का आगमन हुआ। सिन्हा ने विद्यालय भवन, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, वीएसके एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने, स्मार्ट क्लास, व्यवसायिक शिक्षा एवं अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) के संचालन पर विस्तार से चर्चा की। वहीं प्राचार्य अमित भोज ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने विद्यालयों को परिवार की तरह संचालित करने, पेंशन प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण, सेवा पुस्तिका संधारण, दैनिक डायरी लेखन, विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने, स्थानीय लेखा-जोखा एवं एसएमसी गठन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षण गुणवत्ता में सुधार कर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। इस दौरान जिला मिशन समन्वयक डीएमसी सतीश ब्योहारे, एपीसी, झाड़े सर, अंसारी सर एवं प्रोग्रामर नायक भी उपस्थित रहे। डीएमसी ब्योहारे ने संकुल समन्वयकों के दायित्व, शाला प्रवेश उत्सव, पुस्तक स्कैनिंग एवं यू-डाइस संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में विकासखंड के सभी प्राचार्य, संकुल समन्वयक एवं प्रधान पाठक उपस्थित थे।

किसान कांग्रेस की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगी

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिले के किसानों की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चर्चा की गई और एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं वर्तमान में किसान खाद, बीज, बिजली और डीजल की किल्लत से लगातार परेशान हो रहे हैं किसानों की इन्हीं सुलगती समस्याओं को देखते हुए 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आगामी 11 जून को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा वर्तमान भाजपा सरकार में किसान चारों तरफसे परेशान हैं। खाद, बिजली, डीजल और धान खरीदी में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके विपरीत, जब प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तब किसानों को किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत नहीं होने दी गई थी यह सरकार किसान विरोधी साबित हो रही है कांग्रेस के समस्त ब्लॉक अध्यक्षों एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं सभी पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर तैयारी करें और 11 जून 2026 सुबह 11 बजे भारत रत्ना पैलेस के बगल में सभा संबोधित करने पश्चात कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा उक्त घेराव में ताम्रध्वज साहू पूर्व गृहमंत्री , रविंद्र चौबे पूर्व कृषि मंत्री आशीष छाबड़ा पूर्व विधायक एवं अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा की उपस्तिथि एवं गुरुदयाल सिंह बंजारे पूर्व विधायक नवागढ़ घेराव में शामिल रहेंगे एव वरिष्ठ कांग्रेस जनों की विशेष उपस्थिति एवं जिले के समस्त जिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी कार्यकारणी, जिला किसान कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष किसान पदाधिकारी, पूर्व सोसायटी अध्यक्ष (कॉग्रेस) , सेवा दल ,बेमेतरा जिले के समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गण, शहर कांग्रेस अध्यक्ष ,पिछड़ा वर्ग कॉग्रेस, अनुसूचति जाति जन जाति , जिला पँचायत सदस्य, जनपद सदस्य कॉग्रेस समर्थित , पच सरपंच , जिला महिला कांग्रेस, शहर कॉग्रेस , पार्षद पूर्व पार्षद युवा कांग्रेस , एन. यस. यू. आई, के समस्त कांग्रेस प्रकोस्ट की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचें।

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक

दल्लीराजहराजिला। स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में एडीशनल पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक विशेष रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में जिले में सड़क दुर्घटना के रोकथाम के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। एडीशनल एसपी मोनिका ठाकुर ने नशापान एवं तेज गति से ड्राइविंग को सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण मानते हुए पुलिस एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसके लिए पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में ठाकुर ने पुलिस, यातायात एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से जाँच अभियान चलाकर शराब पीकर एवं तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने वालों के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने वाहन चालकों के लायसेंस जांचकर बिना लायसेंस के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। एडीशनल एसपी मोनिका ठाकुर ने जिले में सड़क दुर्घटना के रोकथाम हेतु किए जा रहे उपायों के संबंध में बैठक में उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली। इसके अंतर्गत उन्होंने सड़कों एवं चैक-चैराहों में विचरण करने वाले मवेशियों की रोकथाम के अलावा गुड सेमेरिटन के कार्यों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से जिले में सड़क दुर्घटना के रोकथाम के पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने हेतु सुझाव भी लिया। इस दौरान अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक एवं बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने सड़क दुर्घटना के रोकथाम के उपायों के संबंध में आवश्यक सुझाव भी दिए। बैठक में कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, जिला परिवहन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

वैशाली नगर को विकास की बड़ी सौगात : विधायक रिकेश सेन के प्रयास से 5.25 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

भिलाई नगर। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन के सतत प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रियदर्शिनी परिसर पश्चिम क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ 25 लाख 47 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से क्षेत्र के हजारों नागरिकों को बेहतर सड़क, जल निकासी और मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

वर्षों पुरानी मांगों को मिली स्वीकृति- स्वीकृत राशि से प्रियदर्शिनी परिसर पश्चिम क्षेत्र में पहुंच मार्ग निर्माण, नाली निर्माण एवं विद्युतीकरण जैसे आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। लंबे समय से क्षेत्रवासी इन सुविधाओं की मांग कर रहे थे। विधायक रिकेश सेन ने इन जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार शासन स्तर पर उठाया, जिसके परिणामस्वरूप अब इन विकास कार्यों को मंजूरी मिली है।

विकास को लेकर निरंतर सक्रिय विधायक- वैशाली नगर के समग्र विकास के लिए विधायक रिकेश सेन लगातार राज्य शासन और संबंधित विभागों के संपर्क में रहे। क्षेत्र की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने विकास प्रस्तावों को मजबूती से आगे बढ़ाया और शीघ्र स्वीकृति के लिए निरंतर प्रयास किए। उनकी सक्रियता के चलते यह महत्वपूर्ण परियोजना धरातल पर उतरने जा रही है।

राज्य सरकार व मंत्री का व्यक्त किया आभार- विकास कार्यों की स्वीकृति मिलने पर विधायक रिकेश सेन ने राज्य सरकार तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार की जनहितकारी सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण वैशाली नगर को यह बड़ी सौगात मिली है।

क्षेत्रवासियों को मिलेगा सीधा लाभ- इन विकास कार्यों के पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को बेहतर और सुरक्षित सड़कें, जलभराव से राहत, आधुनिक नाली व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट एवं विद्युतीकरण की सुविधाएं मिलेंगी। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र की सुंदरता और आधारभूत ढांचे में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।

इस स्वीकृति को वैशाली नगर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नवीन नियमों पर कार्यशाला आयोजित

बेमेतरा। स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला पंचायत बेमेतरा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नवीन नियमों एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति एवं सभी जिला पंचायत सदस्यों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े नवीन प्रावधानों, उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान चुनौतियों, पर्यावरणीय प्रभावों तथा उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई 7 प्रशिक्षण सत्र के दौरान कचरे के स्रोत स्तर पर पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, पुनर्चक्रण (री-साइक्लिंग) तथा वैज्ञानिक निस्तारण की प्रक्रियाओं को सरल एवं व्यवहारिक तरीके से समझाया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी पालन न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनप्रतिनिधियों को यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायतें एवं स्थानीय निकाय स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए समुदाय आधारित पहल, जनजागरूकता अभियान तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के सफल मॉडलों एवं नवाचारों की जानकारी भी साझा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन, जनजागरूकता बढ़ाने तथा जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर सहायक संचालक पंचायत भूमिका देसाई सहित जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के सभी समन्वयक, जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नवीन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन, स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यशाला को स्वच्छ एवं विकसित ग्रामों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा गया।

आदिवासी महासम्मेलन स्थगित

दल्लीराजहरा । डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खलारी में 11 जून 2026 को आयोजित होने वाला आदिवासी महासम्मेलन अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतीराम राम कोसमा ने बताया कि यह महासम्मेलन आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण एवं संवैधानिक अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आयोजित किया जाना था। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए क्षेत्रीय विधायक अनिला भेड़िया एवं कांग्रेसजनों द्वारा लगातार बैठकें एवं जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे थे। आयोजन समिति एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जानकारी दी गई है कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। महासम्मेलन की नई तिथि की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी, जिसकी सूचना सभी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन को पृथक रूप से प्रदान की जाएगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दल्ली राजहरा ने क्षेत्र के समस्त कांग्रेसजनों, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए आगामी तिथि घोषित होने पर अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

विकासखण्ड बेरला के ग्राम पंचायत रेवे में समाधान शिविर

बेमेतरा। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जनपद पंचायत बेरला के ग्राम पंचायत रेवे में आयोजित किया गया है। शिविर का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे निर्धारित किया गया है। समाधान शिविर में विभिन्न योजनाओं से पात्र अनेक हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव निराकरण किया जाएगा। शिविर में विभिन्न विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। शिविर में शासन द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने ग्रामीण जनों को शिविर में उपस्थित होकर शिविर का लाभ लेने की अपील की है।

संपादकीय

ईरान-अमेरिका-वार्ता के साथ सैन्य दबाव, शांति की राह में सबसे बड़ी बाधा

एक तरफ समझौते की बात की जाती है, दूसरी ओर सैन्य विकल्प चुनने की धमकी दी जाती है। इस द्वंद्व के बीच शांति कायम होने के सभी दावे धरे रह जाते हैं।ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम की उम्मीद बंधती है और फिर टूट जाती है। यह स्थिति युद्ध शुरू होने के बाद से ही जारी है। पिछले तीन महीने से युद्ध चल रहा है, लेकिन जब शांति वार्ता की बात आती है, तो आमने-सामने और दूरगामी स्थितियों को ध्यान में रखकर संवाद करने की जरूरत नहीं समझी जाती।अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत किसी सहमति के बिंदु पर नहीं पहुंच रही, तो इसे समझने की जरूरत है। दोनों पक्ष जिस तरह अपनी शर्तों पर अड़े हैं, उससे वैश्विक शांति को तो खतरा है ही, दुनिया भर में ऊर्जा संकट भी गहरा रहा है।गौरतलब है कि ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता स्थगित कर दी है। उसने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर यह कदम उठाया है। यह निराशाजनक ही है कि एक तरफ कूटनीतिक कदम उठाने की बात की जाती है, फिर अचानक हमले की स्थिति पैदा कर दी जाती है। पिछले सप्ताह के आखिर में भी अमेरिका ने ईरान के भीतर कई ठिकानों पर बमबारी की। इसके अलावा, लेबनान पर इजराइल के लगातार हमलों से ईरान नाराज है और वह चाहता है कि ये हमले रोक दिए जाएं।हालांकि यह मुद्दा युद्धविराम की मुख्य शर्तों में शामिल है। मगर सवाल है कि अमेरिका युद्धविराम को ताक पर रखकर खुद को या इजराइल को हमले करने से क्यों नहीं रोक पा रहा है। इसमें दोराय नहीं कि अगर दोनों पक्ष गंभीरता से कूटनीतिक पहल करते, तो शांति का कोई रास्ता निकल सकता था। मगर जैसे ही बात आगे बढ़ती है, उसमें दबाव बढ़ाने के साथ रणनीतिक शर्तें जोड़ दी जाती हैं। इससे संवाद के पुल गिर जाते हैं।मौजूदा स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने होर्मुज जलमार्ग पर अपना दबदबा बढ़ाने और उसे सख्ती से बंद करने का संकेत दिया है। समझौते की कवायद कई दिनों से चल रही है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा, तो आखिर इसकी क्या वजह है। स्पष्ट है कि एक तरफ समझौते की बात की जाती है, दूसरी ओर सैन्य विकल्प चुनने की धमकी दी जाती है। इस द्वंद्व के बीच शांति कायम होने के सभी दावे धरे रह जाते हैं। बेहतर हो कि अमेरिका और ईरान स्थायी युद्धविराम और शांति की ओर कदम बढ़ाएं। सैन्य टकराव से आखिरकार कोई समस्या हल नहीं होती।

वर्ष 2017 में लागू जीएसटी को स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में माना जाता है। अनेक अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक राष्ट्र, एक कर की अवधारणा को मजबूत किया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी, कर आधार विस्तृत हुआ और राजस्व संग्रह अधिक व्यवस्थित बना। दिव्य भास्करस्स के अनुसार भारत का जीडीपी वर्ष 2014 के लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। भारत जापान को पीछे छोड़ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि इकानामी सर्वे 2025-26 ने एफबाय 26 में 7.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है। कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक रणनीति का केंद्र बना।

परिवर्तन के 12 वर्ष- विकास, विरासत और वैश्विक नेतृत्व

(डॉ. शिवानी कटारा)

डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले दशक में भारत की आर्थिक और तकनीकी तस्वीर को व्यापक रूप से बदल दिया। भीम ऐप, आधार और यूपीआई जैसी पहलों ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाया, जहाँ आज विश्व के लगभग 49 प्रतिशत रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं।

पिछले 12 वर्षों में भारत ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तनों का एक नया युग देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास ने केवल गति ही नहीं, बल्कि नई दिशा और नई चेतना भी प्राप्त की। आर्थिक सुधारों से लेकर डिजिटल क्रांति, राष्ट्रीय सुरक्षा से सामाजिक समावेशन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक भारत ने आत्मनिर्भरता, सुशासन और वैश्विक प्रतिष्ठा की ओर उल्लेखनीय यात्रा तय की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रारंभ हुई यह यात्रा आज विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय संकल्प में रूपांतरित होती दिखाई देती है।

आर्थिक सुधार और वित्तीय समावेशन – मोदी सरकार की शुरुआती और सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में वर्ष 2014 का मेक इन इंडिया अभियान प्रमुख रहा, जिसने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा प्रदान की। घरेलू उत्पादन, विदेशी निवेश और सरल नियमों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा निर्माण और मोबाइल उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिली।

इसी दौरान अंत्योदय के संकल्प के तहत आर्थिक समावेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को नई पहचान दी। 6.3 करोड़ से अधिक एमएसएमई उद्यमों को सहायता मिली। वहीं, जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 30.80 करोड़ खाते महिलाओं के नाम हैं। 36.73 करोड़ ग्रामीण खातों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान बना।

वर्ष 2017 में लागू जीएसटी को स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में माना जाता है। अनेक अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक राष्ट्र, एक कर की अवधारणा को मजबूत किया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी, कर आधार विस्तृत हुआ और राजस्व संग्रह अधिक व्यवस्थित बना। द्रुस्स्र के अनुसार भारत का जीडीपी वर्ष 2014 के लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। भारत जापान को पीछे छोड़ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि इकानामी सर्वे 2025-26 ने एफबाय 26 में 7.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है।

कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक रणनीति का केंद्र बना। पीएलआई योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सहित 14 रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला, जिससे 5.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ। ईजी आफ डूइंग बिजनेस, जीएसटी सुधार और डिजिटल पारदर्शिता के कारण 2025-26 में रिकॉर्ड 94.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। वहीं, नोटबंदी ने अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद डिजिटल भुगतान, औपचारिक अर्थव्यवस्था तथा काले धन, नकली मुद्रा और आतंक वित्तपोषण पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वहीं, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना ने सहकारी संघवाद, तकनीक-आधारित शासन और प्रशासनिक दक्षता को नई मजबूती प्रदान की।

डिजिटल इंडिया, सामाजिक सशक्तिकरण और आधारभूत विकास - डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले दशक में भारत की आर्थिक और तकनीकी तस्वीर को व्यापक रूप से बदल दिया। भीम ऐप, आधार और यूपीआई जैसी पहलों ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाया, जहाँ आज विश्व के लगभग 49 प्रतिशत रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। पीआई कई देशों में सक्रिय है, जबकि आईएमपीएस और फास्टटेग ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को और गति दी। डीबीटी ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल पारदर्शिता ने सरकारी योजनाओं में लीकेज कम किए तथा लाभार्थियों तक सहायता सीधे पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहलों ने उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान की। इन योजनाओं ने युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को रोजगार खोजने वालों से रोजगार सृजित करने वालों में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और डिजिटल बाज़ार से जोड़कर नई पहचान प्रदान की।

सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जबकि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध हुई। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान ने बालिका शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता को राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप दिया। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब महिलाओं को धुएँ से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ ईंधन, बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की नई दिशा दी। तीन तलाक प्रथा पर रोक लगाकर मुस्लिम महिलाओं को समानता, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की नई सुरक्षा प्रदान की गई।

कृषि क्षेत्र में पीएम किसान योजना के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष सहायता दी गई। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में पीएम गति शक्ति योजना के तहत 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 3.5 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें तथा तीव्र गति से विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्गों ने देश की कनेक्टिविटी को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कीं। नए हवाई अड्डों के निर्माण और 'उड़ान' योजना ने देश की हवाई कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार किया, जबकि वंदे भारत और तेजस जैसी आधुनिक ट्रेनों ने भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को नई गति दी।

शिक्षा क्षेत्र में 2014 के बाद 1,200 से अधिक नए विश्वविद्यालय, 10 नए आईआईटी तथा 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर सामाजिक न्याय के दायरे का विस्तार किया गया, जिससे आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को शिक्षा और रोजगार में नए अवसर प्राप्त हुए।

नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, कौशल-आधारित और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2025 तक 2.27 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एआई,5जी,ड्रोन, साइबर सुरक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में 400 से अधिक आधुनिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। इंडिया एआई मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन ने भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार किया।

आखिर आर्थिक सुनामी के राजनीतिक व आर्थिक मायने मायने क्या हैं?

(कमलेश पांडे)

जानकार बताते हैं कि आर्थिक सुनामी कोई औपचारिक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अर्थव्यवस्था को अचानक और व्यापक झटका लगे तथा उसके प्रभाव दूरगामी हों। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं- जीडीपी वृद्धि दर में तेज गिरावट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी।

राहुल गांधी की आर्थिक सुनामी वाली चेतावनी को फिलहाल एक राजनीतिक चेतावनी और आर्थिक जोखिमों पर विपक्षी आक्रमण के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि उनका यह कहना कि भारत निश्चित रूप से आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ रहा है, अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी होगी। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए इस बहस को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता।

आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि भारत में वास्तव में आर्थिक सुनामी आएगी या नहीं, इसका कोई निश्चित उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हाल में दी गई चेतावनी ने आर्थिक और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी का तर्क है कि वैश्विक संकट, विशेषकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, महंगाई, ईंधन कीमतों और आर्थिक असमानता के कारण भारत एक बड़े आर्थिक झटके की ओर बढ़ सकता है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था के पास पर्याप्त शॉक एब्जॉर्बर हैं–विदेशी मुद्रा भंडार, नियंत्रित महंगाई, खाद्यान्न भंडार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत कर-संग्रह जैसी व्यवस्थाएं–जो बाहरी संकटों का सामना करने में सक्षम हैं।

सवाल है कि क्या सचमुच आर्थिक संकट का खतरा है?– भारत के सामने कुछ वास्तविक चुनौतियाँ हैं- जैसे वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि की आशंका। निर्यात और निवेश पर अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर। रोजगार सृजन की चुनौती। और कृषि और एमएसएमई क्षेत्र पर दबाव। लेकिन साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है, और कई आर्थिक संकेतक अभी व्यापक संकट की पुष्टि नहीं करते।

जानकार बताते हैं कि आर्थिक सुनामी कोई औपचारिक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अर्थव्यवस्था को अचानक और व्यापक झटका लगे तथा उसके प्रभाव दूरगामी हों। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं- जीडीपी वृद्धि दर में तेज गिरावट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। बैंकिंग या वित्तीय संकट। शेयर बाजार में भारी गिरावट। मुद्रा पर दबाव और महंगाई का बढ़ना। निवेश और उपभोग में तीव्र कमी। इतिहास में ग्रेट डीपरेशन (1930 का दशक) और ग्लोबल फायनेंस क्राइस (2008) जैसी घटनाओं को आर्थिक सुनामी के उदाहरण माना जा सकता है।

सवाल है कि क्या भारत में पीएम मोदी के रहते यह आ सकती है?– किसी भी सरकार या प्रधानमंत्री के रहते हुए आर्थिक संकट की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था अनेक घरेलू और वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे– वैश्विक मंदी या वित्तीय संकट। तेल की कीमतों में असाधारण वृद्धि। बड़े युद्ध या भू-राजनीतिक तनाव। प्राकृतिक आपदाएं या महामारी। घरेलू नीति संबंधी गंभीर त्रुटियां। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो बड़े झटकों को सहने में मदद करती हैं– जैसे- विशाल घरेलू बाजार। अपेक्षाकृत मजबूत बैंकिंग और नियामक व्यवस्था। बढ़ता डिजिटल भुगतान तंत्र। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पर निवेश। विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर। दूसरी ओर, चुनौतियां भी मौजूद हैं–जैसे- युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन। कृषि आय में सुधार। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। और, आय असमानता और उपभोग मांग का प्रश्न।

इसलिए निष्पक्ष रूप से कहा जाए तो पीएम मोदी के रहते आर्थिक सुनामी निश्चित रूप से आएगी या कभी नहीं आएगी– दोनों दावे तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं हैं। भारत की आर्थिक स्थिति कई संकेतकों पर अपेक्षाकृत मजबूत दिखती है, लेकिन किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह यह वैश्विक और घरेलू जोखिमों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। आर्थिक सुनामी की संभावना मुख्यतः नीतियों, वैश्विक परिस्थितियों और भविष्य की घटनाओं पर निर्भर करेगी, न कि केवल किसी एक नेता की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर।

आखिर आर्थिक सुनामी के मायने क्या हैं? – आर्थिक सुनामी एक रूपक है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यापक और तीव्र आर्थिक संकट जो समाज, बाजार, उद्योग, रोजगार और सरकार की वित्तीय स्थिति को एक साथ प्रभावित कर दे। जिस प्रकार समुद्री सुनामी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झकझोर देती है, उसी प्रकार आर्थिक सुनामी भी अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर गहरा असर डालती है।

आइए जानते हैं आर्थिक सुनामी के प्रमुख संकेत के बारे में- पहला, शेयर बाजार में भारी गिरावट। दूसरा, निवेशकों की संपत्ति तेजी से घटती है। तीसरा, कंपनियों का बाजार मूल्य कम हो जाता है। चौथा, बेरोजगारी में तेज वृद्धि। पांचवां, उद्योगों और कंपनियों में छंटनी बढ़ती है। छठा, नए रोजगार सृजन की गति धीमी पड़ जाती है। सातवां, बैंकिंग और वित्तीय संकट।

अन्नामलाई का नई पार्टी बनाने का निर्णय आवेश में लिया गया फैसला नहीं, लंबे चिंतन का नतीजा है

तमिलनाडु की राजनीति में एक नया भूचाल उस समय आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा देकर अपने नए राजनीतिक आंदोलन की घोषणा कर दी। यह फैसला तमिलनाडु की जमी हुई राजनीतिक संस्कृति को चुनौती देने वाला एक बड़ा संदेश है। अन्नामलाई ने जिस साफगोई, साहस और वैचारिक दृढ़ता के साथ अपने फैसले को सामने रखा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी दल के सीमित दायरे में नहीं, बल्कि तमिल समाज की व्यापक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में उभरना चाहते हैं।

(नीरज कुमार दुबे)

अन्नामलाई ने खुलकर कहा कि उनके भीतर लंबे समय से यह संघर्ष चल रहा था कि वह पहले भारतीय हैं या तमिल। यह बयान केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के उस मूल द्वंद्व को सामने लाता है जिसमें राष्ट्रीय दलों को अक्सर क्षेत्रीय अस्मिता के सामने संघर्ष करना पड़ता है।

तमिलनाडु की राजनीति में एक नया भूचाल उस समय आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा देकर अपने नए राजनीतिक आंदोलन की घोषणा कर दी। यह फैसला तमिलनाडु की जमी हुई राजनीतिक संस्कृति को चुनौती देने वाला एक बड़ा संदेश है। अन्नामलाई ने जिस साफगोई, साहस और वैचारिक दृढ़ता के साथ अपने फैसले को सामने रखा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी दल के सीमित दायरे में नहीं, बल्कि तमिल समाज की व्यापक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में उभरना चाहते हैं।

अन्नामलाई ने खुलकर कहा कि उनके भीतर लंबे समय से यह संघर्ष चल रहा था कि वह पहले भारतीय हैं या तमिल। यह बयान केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के उस मूल द्वंद्व को सामने लाता है जिसमें राष्ट्रीय दलों को अक्सर क्षेत्रीय अस्मिता के सामने संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि चार दिसंबर 2025 को ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व को इस्तीफे का फैसला बता दिया था, लेकिन उनसे चुनाव तक रुकने का अनुरोध किया गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को लेकर कितना सजग था।

इसे भी पढ़ें- जिसने आज तक नहीं जीता कोई चुनाव, तमिलनाडु में विजय से ज्यादा वो चर्चा में क्यों? अन्नामलाई का गेम और शाह का प्लान, पूरी कहानी कुछ और है

पूर्व पुलिस अधिकारी रहे अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी में सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से प्रवेश किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहते हुए उन्होंने कभी तमिलनाडु की पहचान से समझौता नहीं किया। पिछले अठारह महीनों में संगठनात्मक मामलों को लेकर उनकी असहमति लगातार बढ़ती गई। यही कारण है कि उन्होंने अब एक स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता चुनने का फैसला किया है। यह निर्णय किसी आवेश का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे चिंतन और रणनीतिक तैयारी का हिस्सा दिखाई देता है।

अन्नामलाई ने अपने नए आंदोलन वी द लीडर की घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि उनका उद्देश्य केवल एक और राजनीतिक दल खड़ा करना नहीं, बल्कि राजनीति की भाषा और संस्कृति को बदलना है। उन्होंने परिवारवाद और व्यक्तिपूजा की राजनीति पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि किसी भी विधायक, सांसद या मंत्री का पद स्थायी नहीं होना चाहिए। यह बयान तमिलनाडु की उस परंपरागत राजनीति पर करारा प्रहार है जिसमें कुछ परिवारों और सीमित चेहरों के इर्दगिर्द सत्ता घूमती रही है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्नामलाई ने राजनीति में तकनीकी विशेषज्ञों, युवाओं और सामान्य नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने युवाओं से राजनीति में आने की अपील करते हुए कहा कि अब आम आदमी की नई पीढ़ी की राजनीति की नींव रखी जा रही है। यह सोच उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग करती है। देखा जाये तो तमिलनाडु में जहां लंबे समय से भावनात्मक नारों और जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति चलती रही है, वहां अन्नामलाई प्रशासनिक दक्षता, नैतिकता और प्रतिभा आधारित नेतृत्व की बात कर रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।

उनके आंदोलन के अंतर्गत कोयंबटूर में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फोर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स की स्थापना का फैसला भी बताता है कि वह केवल चुनावी राजनीति नहीं, बल्कि वैचारिक और नैतिक प्रशिक्षण की स्थायी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। यह दृष्टिकोण तमिलनाडु की राजनीति में एक नई बौद्धिक धारा पैदा कर सकता है। उनके आह्वान के कुछ ही समय बाद हजारों लोगों का उनके राजनीतिक आंदोलन से जुड़ना यह संकेत देता है कि जनता के एक हिस्से में बदलाव की बेचैनी पहले से मौजूद थी।

बताया जा रहा है कि अन्नामलाई ने भाजपा नेतृत्व के सामने दो स्पष्ट विकल्प रखे थे। एक तो उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता और अधिकारों के साथ कम से कम सात वर्षों तक प्रदेश नेतृत्व दिया जाए, या फिर उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक राह चुनने दी जाए। यह मांग उनके आत्मविश्वास और दूरदृष्टि दोनों को दर्शाती है। साथ ही इस्तीफे का ऐलान करने से पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से उनकी मुलाकात तथा पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें मनाने की कोशिश इस बात का प्रमाण है कि अन्नामलाई की अहमियत से भाजपा नेतृत्व वाकिफ है।

वैसे तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति भी अन्नामलाई के लिए अवसर लेकर आई है। हालिया विधानसभा चुनावों में द्रविड दलों को झटके लगे और अभिनेता विजय की पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि राज्य की जनता अब पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से बाहर विकल्प तलाश रही है। अन्नामलाई का मानना है कि राष्ट्रीय दलों के लिए यहां सीमित राजनीतिक जगह है, इसलिए एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प ही जनता की आकांक्षाओं को सही दिशा दे सकता है। उनकी यह समझ राजनीतिक रूप से बेहद व्यावहारिक और दूरदर्शी मानी जा रही है।

उधर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भले ही कहा हो कि अन्नामलाई के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक वास्तविकता इससे अलग दिखाई देती है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में भाजपा को ऊर्जा, आक्रामकता और जनस्वीकार्यता दी थी। अब उनके अलग होने से भाजपा के सामने नेतृत्व और जनाधार दोनों की चुनौती खड़ी होगी। दूसरी ओर, अन्नामलाई यदि अपने आंदोलन को संगठित ढंग से आगे बढ़ाते हैं तो वह तमिलनाडु की राजनीति में तीसरी शक्ति के रूप में तेजी से उभर सकते हैं।

बहरहाल, यह स्पष्ट है कि अन्नामलाई ने केवल पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति को नई दिशा देने की चुनौती स्वीकार की है। उनकी राजनीति में साहस है, वैचारिक स्पष्टता है और बदलाव की बेचैनी भी है। आने वाले वर्षों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या उनका यह आंदोलन तमिलनाडु की राजनीति में वैसा ही परिवर्तन ला पाएगा जिसकी वह कल्पना कर रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि अन्नामलाई ने राजनीति के मैदान में एक नई बहस छेड़ दी है और इस बहस को नजरअंदाज कर पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संक्षिप्त समाचार

रायपुर में अवैध डीजल-पेट्रोल कारोबार का भंडाफोड़, 35 लाख से अधिक का ईंधन और टैंकर जब्त, 4 गिरफ्तार

रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के विशेष अभियान के तहत थाना कबीर नगर पुलिस ने अवैध डीजल-पेट्रोल के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 14,100 लीटर पेट्रोल और डीजल, एक टैंकर, नगदी तथा अन्य उपकरण जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 35.45 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कान्हा ढाबा के पीछे स्थित ई.पी. रोलिंग मिल के पास भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का अवैध भंडारण कर उसकी रीसेलिंग और कटिंग का कारोबार संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना कबीर नगर की टीम ने मौके पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी बिना किसी वैध लाइसेंस और दस्तावेज के ज्वलनशील पदार्थों का अवैध एवं असुरक्षित भंडारण कर रहे थे। घेराबंदी कर पुलिस ने चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जब्त सामग्री 8 ड्रम में भरा 1,600 लीटर पेट्रोल 3 ड्रम में भरा 500 लीटर डीजल टैंकर (छ्त्त 07 क्क 8727) में भरा 12,000 लीटर डीजल 1.30 लाख रुपये नगद मोटर पंप, कीप (चाड़ी) एवं कटिंग ड्रम सहित अन्य उपकरण पुलिस के अनुसार जब्त किए गए ईंधन, टैंकर और उपकरणों की कुल कीमत 35,45,770 रुपये है। गिरफ्तार आरोपी ओमप्रकाश साव उर्फ कालिया (38 वर्ष), रायपुर उमेश साव (55 वर्ष), रायपुर रामजी यादव (45 वर्ष), दुर्ग धर्मेन्द्र साव (45 वर्ष), दुर्ग पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस कबीर नगर पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध ईंधन का यह जखीरा कहां से लाया जा रहा था और इसे किन क्षेत्रों में खपाने की तैयारी थी। पुलिस बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने का प्रयास कर रही है।

नौकरी लगने के नाम पर 3 लाख की ठगी, सिपाही गिरफ्तार

रायपुर। पुलिस ने एक सिपाही को लेनदेन के मामले में गिरतार किया है। उस पर दो लोगों के साथ ठगी करने का आरोप है। आरोपी को गिर ?तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।बालको नगर पुलिस थाना ?भारी युवराज तिवारी ने बताया कि इस मामले में दिलेश्वर कर को गिर ?तार किया गया है वह पहले से एक मामले में निलंबित चल रहा था। दिलेश्वर कुछ वर्ष पहले पुलिस की नौकरी में आया था और राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल के रूप में पदस्थ था। जानकारी मिलेगी उसने दो लोगों से यह कहकर तीन लख रुपए वसूल कर दिए थे कि उनकी सरकारी नौकरी लगवा दी जाएगी। कांस्टेबल की बातों ने संबंधित पीडितों को कुछ ऐसा इं ?स किया कि वे उसके झांसी में आ गए और बहुत जल्द धनराशि का भुगतान कर दिया. काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब उनके सपने पूरे नहीं हुई तो उन्होंने पूछताछ की और यहां पता किया।बाद में पीडित को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है। कोरबा जिले के कोरकोमा गांव में रहने वाले निलंबित सिपाही दिलेश्वर कंवर को इसी ?करण में पुलिस ने आज गिर ?तार किया। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दिलेश्वर के साथ एक और व्यि? की गिर ?तारी हुई है जिसने सहयोगी की भूमिका निभाई थी। आरोपियों को कोर्ट भेजने के साथ आगे की कार्यवाही की जाएगी।

खारून रिवर फ्रंट के निर्माण विकास एवं सौंदर्यीकरण के संबंध में बैठक सम्पन्न

रायपुर। लोक निर्माण विभाग द्वारा रूपये 84.15 करोड़ रुपयों की लागत से होने वाले खारून रिवर फ्रंट के निर्माण विकास एवं सौंदर्यीकरण नगर निगम रायपुर द्वारा रूपये 18.86 करोड़ की लागत से किए जाने वाले महादेव घाट जीर्णोद्धार कार्य तथा जल संसाधन विभाग द्वारा रूपये 10 करोड़ की लागत से मां खारुन में किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक आज रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में महापौर श्रीमती मीनल चौबे संबित मिश्रा आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर लोकेश्वर साहू अपर आयुक्त,विनोद पांडे प्रभारी अधीक्षण अभियंता नगर पालिक निगम रायपुर इमरान खान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता राजीव नशीने जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे बैठक में वास्तुकार ने इस सम्बन्ध में बनाए गए प्रजेंटेशन को प्रस्तुत किया । राजेश मूणत ने कहा कि प्रत्येक विभाग आपस में समन्वय कर ले ताकि कार्यों का दोहरीकरण न हो उन्होंने यह भी कहा कि मां खारून रायपुर की जीवनदायनी नदी है और महादेव घाट भगवान शिव का स्थान इसलिए यहां का विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य ऐसा अनुपम तथा सुन्दर रूप से कराया जाय।

घर में नल से साफ पानी आते देखने की खुशी

सहूलियत, सम्मान और सेहत... हर घर नल से बदली जिंदगी-अरूण

रायपुर/ संवाददाता

रोज सुबह उठते ही घर में नल से साफपानी आते देखने की खुशी क्या होती है, इसे कमली से पूछिए। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव को अपने आंगन में लगे नल से आ रहे पानी की धार को दिखाते खुशी से उनकी आंखें डबडबा गईं। जल जीवन मिशन ने कमली जैसी हजारों महिलाओं को अमूल्य खुशियां दी हैं। कभी पीने और निस्तारी के पानी के लिए दिनभर चिंतित रहने वाली इन महिलाओं का जीवन घर में लगे नल ने बदल दिया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव अपने चार दिनों के बस्तर प्रवास के दौरान जल जीवन मिशन का काम देखने कमली के भी गांव पहुंचे। कमली के गांव बस्तर जिले के तोकापाल विकासखण्ड के दुगनपाल में उन्होंने कुछ और घरों में भी जाकर नल से पानी आते देखा। जल जीवन मिशन से घर में पानी पहुंचने की खुशी सभी महिलाओं के चेहरे पर दिख रही थी। जल जीवन मिशन दूरस्थ गांवों

और वनांचलों की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। आधी आबादी के एक बड़े हिस्से को पीने के पानी के लिए रोज जूझना पड़ता था। खासतौर से गर्मियों के दिनों में जब हर साल सिर पर पानी के बर्तन का सफर कुछ सौ मीटरों से कुछ किलोमीटरों में बदल जाता था।जीवन के लिए अनिवार्य जरुरत पानी की व्यवस्था गर्मियों में महिलाओं का जीवन दुष्कर बना देती थी। दुगनपाल में भी महिलाओं को रोज गांव के हैंडपंप या कुआं पर जाकर घर के सभी लोगों के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ता था। घर में नल लग जाने से अब इस समस्या से निजात मिल गई है। जल जीवन मिशन के काम जैसे-जैसे पूरे होते जा रहे हैं, महिलाओं की बाहर से पानी लाने की चिंता और तकलीफ दूर होते जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में अब तक साढ़े आठ हजार से अधिक योजनाओं को पूर्ण कर संचालन के लिए पंचायतों को सौंपा जा चुका है।जल जीवन मिशन महज हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना नहीं है। यह महिलाओं की दिनचर्या और जीवन में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। गांवों में परंपरागत रूप से घर में पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए पानी के इंतजाम का जिम्मा महिलाओं पर ही है। घर तक पानी की पहुंच न होने के कारण उन्हें हैंडपंपो, सार्वजनिक नलों, कुंओं या अन्य स्त्रोतों से रोज पूरे परिवार के लिए जल संग्रहण करना पड़ता है। रोजाना का यह श्रमसाध्य और समयसाध्य काम बारिश तथा भीषण गर्मी के दिनों में और कठिन हो जाता है। कई इलाकों में गर्मियों में जलस्त्रोतों के सूख जाने के कारण दूर-दूर से पानी लाने की मजबूरी रहती है। परिवार के लिए पानी की व्यवस्था हर दिन का संघर्ष बन जाता है। महिलाओं के दिन के कई घंटे इसी काम में निकल जाते हैं। जल जीवन मिशन हर घर तक नल से जल पहुंचाने के साथ ही महिलाओं को कई समस्याओं से निजात दिला रहा है।

महतारी वंदन योजना बनी दुलारी के सफल बिजनेस का आधार

- 9 महीने तक सहायता राशि की बचत कर शुरू किया स्वयं का व्यवसाय
- प्रतिमाह हो रहा 10 हजार रुपये तक शुद्ध लाभ, गांव की अन्य महिलाओं को भी दे रहीं रोजगार

रायपुर। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब केवल घर-गृहस्थी और चूल्हे-चौके तक सीमित नहीं हैं। वे अपने हुनर, कड़ी मेहनत और शासकीय योजनाओं के सहयोग से आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल बन रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है दुलारी माण्डले की, जो महिला कल तक खुद मजदूरी करने को मजबूर थी, आज वह सरकार की योजना के सहारे एक सफल उद्यमी बनकर अन्य लोगों को रोजगार दे रही हैं। दुलरी माण्डले विकासखण्ड आरंग के ग्राम भानसोज की निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वे और उनकी सास ने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली 1 हजार रूपए की सहायता राशि की बचत करना शुरू किया और 9 महीने की जमा राशि 18 हजार रूपए से उन्होंने घरेलु उद्योग की शुरूआत की। ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें इस व्यवसाय हेतु उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यकर्ताओं की सलाह पर दुलारी माण्डले ने अपने पति के सहयोग से बाज़ार से कच्चा माल खरीदा और घर पर ही 'नड्डा एवं मुर्कू' का उत्पादन कर उनकी आकर्षक पैकेज़िग का काम शुरू किया। शुरूआत में दुलारी माण्डले को पैकेज़िग और बाज़ार में बिक्र को लेकर काफी दिक्कतों का समाना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके परिवार ने इस काम में उनका पूरा साथ दिया। उत्पाद के तैयार होने पर उनके बेटे ने सुबह-सुबह आस-पास के गांवों जैसे नारा, कारहीडीह, मालिडीह, फरफौद, डिघारी एवं बरछा इत्यादि गांवों के किराना दुकानों में नड्डा एवं मुर्कू की सप्लाई शुरू किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के मकान का सपना हुआ साकार......

- मेरे संघर्षो को आखिरकार एक पता मिल गया-दसरी बाई साहू

रायपुर। संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर केन्द्र सरकार द्वारा संचालित लोक हितकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ने राजधानी रायपुर शहर क्षेत्र की निर्माण मजदूर दसरी बाई साहू को पक्का घर दिलवाकर उनके व उनके परिवार की दिशा बदल दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा अशोक नगर गुढियारी में रायपुर नगर निगम अंतर्गत डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड कमांक 19 क्षेत्र अंतर्गत निर्माण मजदूर दसरी बाई साहू को पक्का आवास मिलने से उनके परिवार को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि सुरक्षा सम्मान और स्थिरता का आधार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मिल गया है। समाज के जरूरतमंद लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्रतानुसार पक्का आवास देने का काम निरंतर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरूण साव के मार्गदर्शन में नगर निगम रायपुर क्षेत्र में महापौर मीनल चौबे एवं आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देशन में प्रगति पर है। जहाँ अपना घर, वहीं जीवन का भरोसा धूप, धूल और सीमेंट के बीच बीता जीवन.... दूसरों के सपनों को आकार देते देते कब अपने सपनों को इंतजार की आदत पड़ गई, पता ही नहीं चला। दशरी का जीवन बचपन से ही संघों की पाठशाला रहा। न भाई-बहनों का साथ मिला और न ही पिता का साया लंबे समय तक सिर पर रह सका। छोटी-सी उम्र में ही उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाइयों को करीब से देखा। समय के साथ विवाह हुआ।

दुर्गम पहाड़ियों के बीच पहुंची स्वास्थ्य की रोशनी स्वास्थ्य शिविरों ने जगाया भरोसा

भारत मंडपम में आयोजित बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मोदी के 12 वर्ष आदिवासी उत्थान और नक्सलमुक्ति का स्वर्णकाल.....

रायपुर/ संवाददाता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत मंडपम में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 12 वर्ष देश के जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वर्णकाल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी रणनीति के

कारण छत्तीसगढ़ को दशकों पुरानी नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिली। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित जनजातीय समुदाय अब शांति, सुरक्षा और विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। बस्तर में 'नियद नेल्ला नार' और 'बस्तर मुन्ने' जैसे अभियानों के माध्यम से योजनाओं का सैचुरेशन मोड में क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा सुरक्षा शिविरों को 'सेवा डेरा' के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जनजातीय समाज को नई पहचान और सम्मान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हो या धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इन पहलों ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि देश को पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का नेतृत्व करोड़ों आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है।

भीषण गर्मी के चलते छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती हैं गर्मी की छुट्टियां

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने संकेत दिए हैं कि मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल खुलने की निर्धारित तारीख में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल 16 जून 2026 से खुलने वाले हैं। हालांकि जून माह में भी तेज धूप और उमस से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में अभिभावकों के बीच बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि आने वाले दिनों में गर्मी का असर कम नहीं होता है, तो स्कूलों की छुट्टियां कुछ दिनों के लिए और बढ़ाई जा सकती हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों के अनुसार, मौसम की समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग जल्द ही कोई निर्णय ले सकता है।

लखपति दीदी अभियान को मिलेगी नई रफ्तार...

- महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने जिला प्रशासन सक्रिय

रायपुर। संवाददाता

जिला पंचायत सुकमा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुन्द ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बिहान कैडरों, संकुल संगठनों, ग्राम संगठनों के पदाधिकारियों तथा विकासखण्ड एवं जिला बिहान टीम के साथ व्यापक चर्चा की गई। कार्यक्रम में आजीविका गतिविधियों की प्रगति, समूहों के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अद्यतन संधारण तथा संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए सीईओ ठाकुर ने पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्य निष्पादन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने मांग के अनुरूप बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ी तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आगामी तीन दिनों के भीतर शत-प्रतिशत ऑनलाइन लोकोस एंट्री, लखपति दीदी एंट्री तथा संकुल स्तरीय संगठनों के दैनिक लेन-देन का रिकॉर्ड पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मुकुंद ठाकुर ने लखपति दीदी पहल के तहत चिन्हित ग्रामों के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर उन्हें जल्द से जल्द 'लखपति दीदी ग्राम' के रूप में विकसित करने पर बल दिया।

सतनाम भवन में समाधान शिविर का हुआ आयोजन

समाधान शिविर जनता के बीच समाधान का मजबूत सेतु-मोहले

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित सतनाम भवन में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों और नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। शिविर में विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों को आमजनों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। शिविर में नुक्कड़-नाटक के माध्यम से स्वच्छता, कचरा पृथक्करण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए नागरिकों को घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे, सेनेटरी वेस्ट तथा स्पेशल केयर वेस्ट को अलग-अलग रखने तथा वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन में सहयोग करने का संदेश दिया गया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान ही वास्तविक सुशासन है। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने राशन वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ई-केवाईसी कराने पर जोर दिया तथा बिजली चोरी पर

प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र सभी हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। विधायक ने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर जिला प्रशासन को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व विद्युत व्यवस्था के आवश्यक मेंटेनेंस कार्य पूर्ण करने तथा बिजली संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सुशासन तिहार के सफल संचालन में योगदान देने वाले सभी अधिकारी-कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री एवं स्वीकृति पत्र वितरित कर लाभान्वित किया गया। पांच किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत कुल 03 लाख 38 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। इसके अलावा श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, राशन कार्ड एवं मत्स्य जाल का वितरण किया गया। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

संक्षिप्त समाचार

राशनकार्ड के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर,सेवा-सेतु पोर्टल से करें आवेदन

रायपुर। जिले के आम नागरिकों के लिए राशनकार्ड संबंधी सेवाओं को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने सेवा-सेतु पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं नि:शक्तजन श्रेणी के नवीन राशनकार्ड जारी कराने, राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने तथा नाम विलोपन के लिए नागरिक स्वयं घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह सुविधा सभी लोक सेवा केंद्रों के साथ-साथ स्थानीय निकायों और आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है।ला खाद्य अधिकारी रविशंकर कोमरा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान हितग्राही को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसके बाद आवेदन रसीद क्रमांक स्वत: जनरेट होगा। लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन करने पर निर्धारित 30 रुपये शुल्क देय होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा जांच, अनुशंसा और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रकरण स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेजा जाएगा। नियमानुसार परीक्षण एवं पात्रता की पुष्टि के उपरांत राशनकार्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे।राशनकार्ड स्वीकृत होने के बाद उसका पीडीएफऑनलाइन जनरेट किया जाएगा, जिसे संबंधित कार्यालय अथवा लोक सेवा केंद्र से प्रिंट कर हितग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा। हितग्राही स्वयं भी सेवा-सेतु पोर्टल से राशनकार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राशनकार्ड प्राप्त करने के बाद मुखिया एवं सभी दर्ज सदस्यों को उचित मूल्य दुकान में ई-पॉस मशीन अथवा फेस ई-केवाईसी के माध्यम से अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराना होगा, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके।

रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने रेडक्रॉस सोसाइटी के लिए दी सहयोग राशि

रायपुर। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (राडा) ने रेडक्रॉस सोसाइटी के लिए 1 लाख रूपए की सहयोग राशि कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को सौंपा। इस अवसर पर रायपुर ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसिएशन (राडा) के अध्यक्ष रविंदर भसीन, उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक गर्ग तथा अभिनव ऋषि उपस्थित थे। रेडक्रॉस सभाकक्ष में कार्यक्रम के दौरान राडा के अध्यक्ष रविंदर भसीन ने कलेक्टर डॉ. सिंह को संस्था द्वारा समय-समय पर किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों एवं सीएसआर गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राडा केवल ऑटोमोबाइल व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी निरंतर निर्वहन करती रही है। हाल ही में संस्था द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए संचालित विद्यालय को एक बस प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त राडा द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, हेलमेट जागरूकता कार्यक्रम, यातायात सुरक्षा से जुड़े विभिन्न आयोजन तथा अन्य अनेक सामाजिक एवं जनहितकारी गतिविधियां लगातार संचालित की जाती रही हैं। कलेक्टर ने राडा के इस योगदान के लिए संस्था का आभार व्यक्त किया तथा समाज सेवा के प्रति उसकी सकारात्मक सोच और निरंतर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं व्यापारिक संस्थाओं की ऐसी सहभागिता समाज के कमजोर वर्गों तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दौरान निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, आरटीओ आशीष देवांगन तथा सीएमएचओ डॉ मिथलेश चौधरी उपस्थित रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सनसनीखेज खुलासा, पीड़िता के दादा समेत 3 गिरफ्तार

रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए पीड़िता के दादा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए आरोपियों से 1.30 लाख रुपये की रकम ली गई थी।जानकारी के अनुसार, चौकी सिलयारी क्षेत्र में 18 अप्रैल 2026 को दर्ज दुष्कर्म प्रकरण की गहन विवेचना के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। जांच में पता चला कि पीड़िता के दादा ने आरोपी ईश्वर घृतलहरे के परिजनों से घटना को छिपाने के एवज में 1 लाख 30 हजार रुपये नकद प्राप्त किए थे। इस लेन-देन का वीडियो भी सामने आया है। इतना ही नहीं, दूसरे आरोपी को फोन कर धमकाने की बात भी जांच में उजागर हुई है।पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच के दौरान पीड़िता के दादा ने अपनी नातिन के साथ किसी भी प्रकार की घटना होने से इनकार किया था। बाद में शासन से मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी मिलने पर उन्होंने मामले की पुन: जांच कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। मामले में गंभीर लापरवाही और धन लेकर अपराध दबाने के आरोप में पुलिस ने पीड़िता के दादा, सीताराम मेडिकल स्टोर के संचालक चन्द्रशेखर यदु और टुकेन्द्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दादा के पास से 1 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं, दुष्कर्म के दोनों मुख्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले की जांच जारी है।

अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई : तीन चैन माउंटेन मशीन और एक हाईवा वाहन जप्त

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में खनिज संसाधनों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग की केंद्रीय खनि उड़नदस्ता एवं जिला स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा जिला गरियाबंद में बड़ी कार्रवाई की गई है।खनिज विभाग के सचिव और संचालक के निर्देशानुसार केंद्रीय खनि उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने दिनांक 08 जून 2026 को औचक निरीक्षण के दौरान जिला गरियाबंद के तहसील राजिम अंतर्गत ग्राम कुरुसकेरा स्थित पैरी नदी में गौण खनिज साधारण रेत के अवैध उत्खनन एवं मशीनों के माध्यम से नियम विरुद्ध रेत उत्खनन का मामला पाया। जांच के दौरान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए तीन चैन माउंटेन मशीनों को जप्त कर सील किया गया। साथ ही खदान संचालक एवं मशीन मालिकों को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभागीय समन्वय

छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में लाना हमारा लक्ष्य

- डेटा आधारित नीति निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर
- बस्तर अंजोर के माध्यम से बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने की दिशा में होंगे नवाचारपूर्ण प्रयास

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ''अंजोर विजन-2047'' के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल योजनाओं के निर्माण से नहीं, बल्कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सटीक आंकड़ों पर आधारित नीति निर्माण और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति से संभव होगा। नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग में आयोजित स्टेट सपोर्ट मिशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट एवं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट्स के इंडक्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार ''अंजोर विजन-2047'' राज्य के दीर्घकालिक विकास का व्यापक रोडमैप है, जिसमें आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक प्रगति, निवेश संवर्धन और मानव विकास से जुड़े स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य और अंजोर विजन-2047 एक-दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों का मूल उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को

अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को इन लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्वित करना होगा। इस दिशा में राज्य नीति आयोग के अंतर्गत गठित स्स्रू क्ष्ह्ल एवं रू॰श्व इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। श्री मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने नीति आयोग के स्ष्ठत्र इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अब राज्य का लक्ष्य केवल सूचकांकों में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाना है। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास, महिला श्रम भागीदारी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य नीति आयोग के साथ कार्य कर रही विशेषज्ञ टीमों को विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर चक्ष्ह्ल आधारित समीक्षा, नीति विश्लेषण, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा साक्ष्य आधारित सुझावों के माध्यम से विकास की गति को और तेज करना होगा। उन्होंने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से नवाचार, जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया। उपाध्यक्ष श्री मिश्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और राज्य नीति आयोग के संयुक्त प्रयासों से अंजोर विजन-2047 के लक्ष्य निर्धारित समयावधि में प्राप्त किए जा सकेंगे तथा छत्तीसगढ़ समावेशी, सतत और विकसित राज्य के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के उस संकल्प का उल्लेख किया, जिसमें बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने की बात कही गई थी। श्री मिश्रा ने कहा कि बस्तर संभाग राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

खेत बचाओ अभियान में जुटे 300 किसान जैविक खेती को लेकर जागरूकता सम्मेलन

- रासायनिक खेती छोड़ जैविक खेती अपनाएं, यही भविष्य की खेती: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर/ संवाददाता

जैविक खेती मिशन योजना के अंतर्गत खेत बचाओ अभियान के तहत मनेंद्रगढ़ ने एक दिवसीय जिला स्तरीय जागरूकता एवं कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले भर से लगभग 300 किसानों ने भाग लेकर जैविक एवं प्राकृतिक खेती, उन्नत कृषि तकनीकों तथा मृदा संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, जनप्रतिनिधियों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को खेती की बदलती चुनौतियों और उनके समाधान से अवगत कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल थे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार कम हो रही है, जिसका असर फसलों की गुणवत्ता के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करते हुए जैविक और प्राकृतिक

खेती की ओर अग्रसर हों। उन्होंने कहा कि जैविक खेती केवल खेती की पद्धति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक समृद्धि का आधार है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने किसानों से इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ खेती करने का आग्रह किया। उद्यानिकी महाविद्यालय चिरमिरी से आए वैज्ञानिक सुजीत कुमार राय एवं शुभम कुमार ठाकुर ने किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों, उन्नत फसल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा उत्पादन बढ़ाने के प्रभावी उपायों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने किसानों को बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप कृषि पद्धतियां अपनाने की सलाह दी। कृषक सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना तथा कृषि को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाना रहा।

जल जीवन मिशन ने बदली जशपुर के वनांचल ग्राम पुटुकेला की तस्वीर

- 60 किलोमीटर दूर स्थित गांव में अब हर घर तक पहुंच रहा शुद्ध पेयजल, 134 परिवारों को मिली बड़ी राहत

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित जल जीवन मिशन दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में भी जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड स्थित ग्राम पुटुकेला इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है, जहां आज प्रत्येक परिवार को घर पर ही नल के माध्यम से नियमित शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे इस वनांचल ग्राम में भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद जल जीवन मिशन के अंतर्गत सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था विकसित की गई है। ग्राम में स्थापित चार उच्च स्तरीय जलागारों के माध्यम से 134 फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शनों द्वारा सभी परिवारों तक नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से पहले ग्रामवासी पेयजल के लिए कुओं एवं अन्य पारंपरिक जल स्रोतों पर निर्भर थे। महिलाओं और बच्चों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर पानी लाना पड़ता था, जिससे समय और श्रम दोनों की अधिक खपत होती थी। गर्मी के मौसम में जल स्रोतों में पानी की कमी और वर्षा ऋतु में जल की गुणवत्ता प्रभावित होने से ग्रामीणों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही जलजनित बीमारियों का खतरा भी बना रहता था। मिशन के तहत पाइपलाइन नेटवर्क बिछाकर प्रत्येक घर तक नल कनेक्शन पहुंचाया गया है। अब ग्रामीणों को पेयजल के लिए दूर-दराज के स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। घर पर ही नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होने से ग्रामीणों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता से महिलाओं और बच्चों के समय तथा श्रम की बचत हुई है। बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जा पा रहे हैं, वहीं महिलाएं घरेलू कार्यों के साथ-साथ आजीविका संबंधी गतिविधियों में भी अधिक समय दे पा रही हैं। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होने से ग्रामीणों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है तथा जलजनित बीमारियों में कमी दर्ज की गई है। जल जीवन मिशन के निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी परिवारों को नियमित नल जल सुविधा उपलब्ध कराए।

अधिकारी-कर्मचारियों से पीएम सूर्यघर योजना का लाभ लेने किया आग्रह.....

- नैनो डीएपी व यूरिया के उपयोग के लिए अभियान चलायें, किसानों को करें प्रोत्साहित
- बारिश से पहले विद्युत विभाग व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश

रायपुर/ संवाददाता

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सोसायटी सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि कृषि विभाग के सभी आरएईओ फील्ड में निरंतर जाएं और किसानों को नैनो डीएपी व यूरिया के उपयोग के लिए किसानों

को प्रोत्साहित करें और जिले में इसे एक अभियान के रूप में चलाएं। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा पीएम सूर्यघर योजना का लाभ सभी अधिकारी-कर्मचारी उठाएं एवं सभी अधीनस्थ और आमजनों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके माध्यम से हम बिजली की बचत कर सकते हैं और बिजली उत्पादक भी बन सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि विद्युत विभाग बारिश के पूर्व सभी तैयारी रखें ताकि आम जनता को लंबे समय तक विद्युत अवरोध का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्वास्थय विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड अधिक से अधिक बनाएं ताकि इस योजना का हितग्राहियों को लाभ मिले। महिला एवं बाल विकास विभाग से महतारी वंदन योजना के ई-केवायसी एवं कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं की बैठक लें व कार्य योजना बनाएं।बैठक में नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, एडीएम उमाशंकर बंदे, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर एवं अपर कलेक्टर मनीष मिश्रा सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

अवैध मटन-चिकन दुकान पर निगम की कार्रवाई, सामान जब्त

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध रूप से संचालित मटन-चिकन दुकान के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। तेलीबांधा क्षेत्र में जे.आर. नायडू स्कूल के पीछे चल रही अवैध दुकान पर निगम के जोन क्रमांक-3 की टीम ने अभियान चलाकर सामान जब्त किया और अतिरिक्त क्षेत्र में लगाए गए टिन शेड को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया। जानकारी के अनुसार, नगर निवेश विभाग को इस संबंध में जनशिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-3 की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जोन कमिश्नर प्रीति सिंह, कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता नरेश साहू और उपअभियंता अक्षय भारद्वाज मौजूद रहे।

चर्चेड़ी में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर लिया भाग, योजनाओं की मिली जानकारी

सुशासन तिहार के शिविर में उमड़ा जनसैलाब हितग्राही हुए लाभान्वित

- शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 471 हित ग्राहियों को लाभान्वित किया गया
- अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति और लाभ वितरण की जानकारी ली

रायपुर/ संवाददाता

सुशासन तिहार के अंतिम जनसमस्या निवारण शिविर में आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के चर्चेड़ी ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। आसपास की 18 ग्राम पंचायतों के लोगों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए तथा शासन

की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर आयोजित सुशासन तिहार जनसेवा का प्रभावी माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। शिविर में राजस्व विभाग से संबंधित 128 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन अधिकार पट्टा, महतारी वंदन योजना, विद्युत कनेक्शन, बोरवेल, हैंडपंप और अन्य जनहितकारी योजनाओं से जुड़े 770 आवेदन जमा किए गए। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने कहा कि सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से राजस्व प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने की अपील की ताकि मामलों का समयबद्ध निराकरण हो सके। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 471 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इनमें 150 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा, 49 हितग्राहियों को आबादी पट्टा, 28 किसानों को किसान किताब, 120 लोगों को वोटर आईडी, 2 कोटवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पंडरी और पथर्री ग्राम पंचायतों में पूर्ण हुई नल-जल योजना का हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रदान किया। ग्रामोद्योग विभाग ने दो हितग्राहियों को 35 हजार एवं 70 हजार रुपये की अनुदान राशि वितरित की। परिवहन विभाग ने 32 लोगों को लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए। स्वास्थ्य, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा कृषि विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, सिकल सेल कार्ड, सहायक उपकरण, मूंग बीज, सुकन्या समृद्धि योजना और नोनी सुरक्षा योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

पीएम मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा किया गया कार्यक्रम आयोजित

किरन्दुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राम मंदिर परिसर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के विकास, सुशासन, महिला सशक्तिकरण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित महिलाओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की तथा उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बहनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रहित एवं समाज सेवा के

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा मंडल किरंदुल ने चलाया स्वच्छता अभियान, किया वृक्षारोपण

केंद्र सरकार के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा मंडल किरंदुल द्वारा स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता के निर्देशानुसार तथा भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सोढ़ी के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह एवं पूर्व श्रम आयोग सदस्य आर.नाहक ने किया। स्वच्छता अभियान के तहत हनुमान टेकरी, अटल परिसर एवं गौठान क्षेत्र में साफ-सफाई की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया तथा नागरिकों से अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने की अपील की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण आधार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनभागीदारी आधारित अभियानों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में भाजपा मंडल के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा के सदस्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

दूसरे दिन भी ईंधन संकट बरकरार, अधिकांश पेट्रोल पंप बंद, एकमात्र फ्यूल प्वाइंट पर पुलिस तैनात

कोण्डागांव। जिला मुख्यालय कोण्डागांव में ईंधन संकट के हालात दूसरे दिन भी बने हुए हैं। शहर में स्थित अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक समाप्त हो जाने से वे बंद पड़े हैं, जबकि एकमात्र संचालित फ्यूल प्वाइंट पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पेट्रोल पंप परिसर में पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई।

जानकारी अनुसार, कोण्डागांव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एचपी) के पांच, इंडियन ऑयल के दो तथा भारत पेट्रोलियम का एक फ्यूल रिफिल प्वाइंट संचालित है। इनमें से अधिकांश पंपों पर ईंधन समाप्त हो चुका है, जिसके कारण वे बंद हैं। बस स्टैंड के पास स्थित ज्योति पेट्रोल पंप में गुरुवार सुबह एक टैंकर से पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति हुई थी, लेकिन सुबह से उमड़ी भारी भीड़ के चलते दोपहर तक पूरा स्टॉक समाप्त हो गया। अगली आपूर्ति कब पहुंचेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी पंप प्रबंधन के पास भी नहीं है इधर शहर के नारंगी नदी के पास स्थित दिनेश इंडियन ऑयल फ्यूल प्वाइंट पर फिलहाल पेट्रोल और डीजल दोनों उपलब्ध हैं। फ्यूल प्वाइंट संचालक दिनेश जैन ने बताया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को लगातार आपूर्ति की जा रही है। हालांकि बढ़ती भीड़ और संभावित अव्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने फ्यूल प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात किया है। साथ ही डिब्बों में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगा दी गई है। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार दोपहिया वाहनों को अधिकतम 200 रुपये, चारपहिया एवं अन्य वाहनों को 1000 रुपये तथा आवश्यक परिस्थितियों में बड़े वाहनों को अधिकतम 2000 रुपये तक का ईंधन दिया जा रहा है। ईंधन संकट के चलते आम नागरिकों, किसानों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों की नजर अब ईंधन की नई खेप और अन्य पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति बहाल होने पर टिकी हुई है।

कोण्डागांव में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्री बीएड और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, 8 केंद्रों में शामिल हुए 1581 परीक्षार्थी

कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्री बीएड एवं बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षाएं गुरुवार को कोण्डागांव जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के लिए जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। डिप्टी कलेक्टर एवं व्यापम परीक्षा नोडल अधिकारी रश्मि पोया ने बताया कि, कुल 8 परीक्षा केंद्रों में से 5 केंद्र प्री बीएड परीक्षा तथा 3 केंद्र बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए थे। उन्होंने बताया कि, प्री बीएड परीक्षा में कुल 1479 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1063 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं बीएससी नर्सिंग प्रवेश

परीक्षा में 769 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 518 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इस प्रकार दोनों परीक्षाओं में कुल 2248 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 1581 अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

नारायणपुर। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं वंश वृद्धि को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा 3 उपधारा 2 के तहत इस अवधि में प्रदेश के अधिकांश जल संसाधनों में मत्स्याखेट (मछली पकड़ना) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश के सभी नदी, नाले, जलाशय एवं अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में 16 जून से 15 अगस्त तक किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध मछलियों के प्रजनन काल के दौरान उनके संरक्षण एवं मत्स्य संपदा के संवर्धन के उद्देश्य से लगाया गया है। हालांकि यह नियम उन छोटे तालाबों एवं जल स्रोतों पर लागू नहीं होगा जिनका संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है। इसके अलावा जलाशयों में संचालित केज कल्चर गतिविधियों को भी इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। मत्स्य विभाग ने आमजन एवं मछुआरा समुदाय से बंद ऋतु के दौरान नियमों का पालन करने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025 के तहत छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1948 की धारा 5 के अनुसार उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मत्स्य विभाग का कहना है कि बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट पर रोक लगाने से मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भविष्य में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी और मछुआरा समुदाय को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। विभाग ने

पं.विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि

कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश के विकास पुरुष के रूप में पहचान रखने वाले स्वर्गीय पंडित विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि पर जिला मुख्यालय कोंडागांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनों ने उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को स्मरण किया तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल ने अपना संपूर्ण जीवन जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया। वे छत्तीसगढ़ की राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और प्रदेश को विकास की नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों और विचारों से आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है।श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पंडित

विद्याचरण शुक्ल ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, संचार एवं आधारभूत संरचनाओं के विस्तार के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उनका राजनीतिक जीवन संघर्ष, समर्पण और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा है। उन्होंने सदैव समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज़ को बुलंद किया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने वर्ष 2013 में हुए नक्सली हमले में उनकी शहादत को याद करते हुए कहा कि लोकतंत्र और जनसेवा के प्रति उनकी निष्ठा सदैव स्मरणीय रहेगी। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई एवं कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। सभी ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रितेश पटेल जिला महामंत्री,जिला उपाध्यक्ष तरुण गोलछा,प्रदेश सचिव सकुर खान,शहर अध्यक्ष नरेंद्र देवांगन,ब्लॉक अध्यक्ष संजय करन,उपाध्यक्ष कमलेश दुबे,महामंत्री सनी चोपड़ा,महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव तबस्सुम बानो, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष तबस्सुम बानो, महिला कांग्रेस नेत्री नीलू देवांगन,लेखनी प्रधान, रंजीता अग्रवाल,युवा नेता हितेश ढीमर, डीके नायक, गोलू पटेल सहित कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पत्रकारों की सुरक्षा एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

कोण्डागांव। जिले के विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों ने महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोंडागांव को सौंपकर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके प्रति निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवहार की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले के पत्रकार शासन-प्रशासन की योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े विषयों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर भी समाचारों का प्रकाशन करते हैं। पत्रकारों का कहना है कि वे अवैध गतिविधियों, जनसमस्याओं, पर्यावरणीय मुद्दों, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों तथा अन्य सार्वजनिक हित के मामलों को भी समाचार माध्यमों के जरिए सामने लाने का कार्य करते हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कई बार जनहित से जुड़े मामलों में शिकायतों और आवेदनों पर कार्रवाई में विलंब देखने को मिलता है, जबकि पत्रकारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई किए जाने की

धारणा मीडिया कर्मियों के बीच बनी हुई है। पत्रकारों ने इस स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष एवं समान व्यवहार की अपेक्षा जताई है। पत्रकारों ने हाल ही में सामने आए एक घटनाक्रम का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार समाचार संकलन के दौरान एक पत्रकार के साथ प्रशासनिक स्तर पर की गई कार्रवाई से पत्रकार समुदाय में असंतोष व्याप्त है। पत्रकारों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा भविष्य में मीडिया कर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने शासन एवं प्रशासन से अनुरोध किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि मीडिया कर्मी निर्भीक एवं निष्पक्ष रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ पत्रकार शैलेश शुक्ला, पूनम मानिकपुरी , विजय साहू, संजय सोनपिपरे,गिरीश जोशी, मनोज शर्मा, रितेश पटेल सहित अन्य पत्रकार उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनी वरदान: छबीला यालम को मिला सम्मानजनक विवाह और आत्मनिर्भरता का संबल

बीजापुर। जिला बीजापुर के भोपालपटनम परियोजना अंतर्गत ग्राम मेट्टुपल्ली की बेटी छबीला यालम के जीवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार किया है। आर्थिक रूप से साधारण किसान परिवार से संबंध रखने वाली छबीला के लिए यह योजना न केवल सम्मानजनक विवाह का माध्यम बनी, बल्कि आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव भी साबित हुई।

आर्थिक तंगी के बीच बेटी के विवाह की चिंता: छबीला के पिता बाबू यालम एवं माता सरिता यालम अपनी बेटी को पढ़ा-लिखाकर आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। लेकिन जैसे-जैसे विवाह का समय नजदीक आया, सीमित आय के कारण विवाह के खर्चों को लेकर परिवार चिंतित रहने लगा। सामाजिक रीति-रिवाजों, भोज और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च परिवार की क्षमता से बाहर प्रतीत हो रहा था।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दिखाई राह

इसी दौरान क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला मट्टी ने परिवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी 2026 को बीजापुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जानकारी मिलते ही परिवार ने 25 जनवरी 2026 को आवेदन कर दिया।

सामूहिक विवाह में संपन्न हुआ गरिमामय विवाह

योजना के तहत ग्राम मेट्टुपल्ली निवासी पवन वासम के साथ छबीला यालम का विवाह 10 फरवरी 2026 को बीजापुर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में पूर्ण हिंदू रीति-रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। समारोह में वर-वधू और उनके परिवारों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया तथा विवाह की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शासन द्वारा सुनिश्चित की गईं।

50 हजार की सहायता बनी आत्मनिर्भरता की राह

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत छबीला को कुल 50,000 की सहायता प्राप्त हुई, जिसमें 15,000 मूल्य की उपहार सामग्री एवं आयोजन व्यय तथा 35,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की गई। छबीला ने इस राशि का सदुपयोग करते हुए सिलाई मशीन खरीदी और स्वरोजगार की शुरुआत की। आज वे सिलाई कार्य के माध्यम से स्वयं आय अर्जित कर रही हैं। कुछ राशि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि को उन्होंने भविष्य की सुरक्षा के लिए बैंक में जमा कर रखा है।

सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण का उदाहरण

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुधार का भी प्रभावी माध्यम बन रही है। सामूहिक विवाह से अनावश्यक खर्च और दहेज जैसी कुरीतियों पर अंकुश लग रहा है, वहीं विभिन्न समुदायों और परिवारों के बीच सामाजिक समरसता एवं भाईचारे को भी बढ़ावा मिल रहा है।

बेटी के सपनों को मिले नए पंख

आज छबीला यालम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने नव-वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर चुकी हैं। स्वरोजगार के माध्यम से वे आर्थिक रूप से सशक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने उनके परिवार की वर्षों पुरानी चिंता को दूर कर एक सुरक्षित, सम्मानजनक और उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने छबीला यालम के जीवन में खुशियों की नई शुरुआत की है, जहां सम्मानजनक विवाह के साथ आत्मनिर्भरता का सपना भी साकार हो रहा है।

स्कूल खुलने से पहले सभी तैयारियां पूरी करें, बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: कलेक्टर अभिजीत सिंह

जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रबंधकों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

दुर्ग। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हुडको भिलाई में जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रबंधकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्कूल खुलने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए बताया कि शासकीय हाई स्कूलों में पुस्तकें पहुंच चुकी हैं, जबकि सेजस एवं निजी विद्यालयों में अगले तीन-चार दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने स्कूल परिसरों की साफ-सफाई, पेयजल, वॉटर फिल्टर, शौचालय, पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जर्जर भवनों को अनुमति लेकर डिस्मेंटल करने और मरम्मत योग्य भवनों की शीघ्र मरम्मत कराने को कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई। उन्होंने स्कूल बसों की नियमित जांच और चालकों की मॉनिटरिंग करने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा स्कूलों में नशामुक्ति अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने सभी को हेलमेट पहनने, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने एवं वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रखने की अपील की, जिससे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। कलेक्टर सिंह ने स्कूलों में 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी एवं 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण हेतु बच्चों एवं अभिभावकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिभावकों की सहमति प्राप्त कर अधिक से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में प्रभावी है और केवल एक बार लगाया जाएगा। बैठक में विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट कार्य की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 96 प्रतिशत बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट हो चुका है। शेष बच्चों का कार्य पूरा करने के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी प्राचार्यों को समन्वय बनाकर सितंबर तक शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। समीक्षा बैठक में जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना ने विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाओं की आशंका को देखते हुए सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए फायर सेफ्टी मॉकड्रिल आयोजित की जाए।

सुशासन तिहार में भी नहीं हुआ क्षतिग्रस्त सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, ग्रामीणों में नाराजगी

अम्लेश्वर/पाटन। जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत ग्राम पंचायत पाहंदा (अ) में स्थित क्षतिग्रस्त सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तक नहीं हो सका है। यह स्थिति तब है जब प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण का दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गांव-गांव में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों को घरों में शौचालय निर्माण के लिए अनुदान राशि भी प्रदान की गई, ताकि गांव स्वच्छ एवं सुंदर बन सकें। इसके बावजूद ग्राम पंचायत पाहंदा (अ) में पंचायत मुख्यालय के समीप बाजार चौक स्थित सार्वजनिक शौचालय वर्षों से क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार शौचालय का निर्माण पूर्ण होने के बाद उसका विधिवत लोकार्पण भी नहीं हो पाया था। इसी दौरान सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत शौचालय के एक हिस्से को तोड़ दिया गया और बाद में उसे उसी हालत में छोड़ दिया गया। वहीं पाहंदा से अम्लेश्वर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होकर सड़क चकाचक बन गई, लेकिन शौचालय की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच तथा अन्य जनप्रतिनिधि इस समस्या के समाधान में असफल साबित हो रहे हैं। क्षतिग्रस्त भवन के संपर्क में छोटे-छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा शौचालय परिसर में कूड़ा-कचरा फेंके जाने से स्वच्छता व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग एवं ब्लॉक स्तर के जिम्मेदार अधिकारी भी इस गंभीर समस्या को लेकर मौन साधे हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त सार्वजनिक शौचालय का शीघ्र निर्माण कराया जाए तथा परिसर की नियमित साफ -सफाई सुनिश्चित की जाए।आप चाहें तो मैं इसे स्थानीय समाचार पत्र की शैली में और अधिक प्रभावशाली तथा प्रकाशन योग्य रूप में भी तैयार कर सकता हूँ।

यातायात व्यवस्थाओं में सुधार एवं सड़क दुर्घनाओं के रोकथाम को लेकर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न

विभागों द्वारा की गयी कार्यों के अद्यतन प्रगति की समीक्षा

दुर्ग। जिले में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वरिष्ट पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी शामिल हुए। बैठक के प्रारंभ में विगत बैठक के पालन प्रतिवेदन की विभागवार समीक्षा की गयी। जिसमें अधिकारियों ने कार्य पूर्ण होने, अद्यतन प्रगति एवं की गयी विभागीय कार्यवाहियों की जानकारी दी। साथ ही जिले की सड़कों में यातायात सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार-विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। कलेक्टर सिंह ने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार अधिकारियों को सौंपे गए विभागीय कार्य, रिफ्लेक्टर, स्पीड ब्रेकर एवं स्ट्रीट लाईट लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लोक निर्माण विभाग (भ./स. एवं वि./या.) को दुर्घटनाजन्य स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा भिलाई इस्पता संयंत्र वाहनों के लिए भारतमाला सड़क से जोड़ने, भारतमाला सड़क पर पुरई के पास बोगदा की हाइट बढ़ाने, भिलाई में केनाल रोड निर्माण तथा बारिश के पूर्व सभी अण्डरब्रिजों की सफाई एवं आवश्यक मरम्मत पर भी चर्चा की गयी। बैठक में एडीएम वीरेन्द्र सिंह, एएसपी यातायात सुत्रध्वा मिश्रा, नगर निगम आयुक्त भिलाई राजीव पाण्डेय, नगर निगम आयुक्त दुर्ग सुमीत अग्रवाल, एसडीएम दुर्ग हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम भिलाई/भिलाई-03 महेश राजपूत, एसडीएम धमधा सोनल डेविड सहित लोक निर्माण विभाग, परिवहन, विद्युत विभाग, एनएचएआई, एनएचआई, पुलिस विभाग और बीएसपी के अधिकारीगण उपस्थित थे।

नारकोटिक्स नियंत्रण अभियान के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

नशीली पदार्थ तस्करों की जानकारी टोल फ्री नं. 1933 में दे सकते हैं

दुर्ग। जिले में नारकोटिक्स नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले में मादक पदार्थों के रोकथाम, नशा मुक्ति केन्द्रों की व्यवस्थाओं तथा संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की गई। बैठक में वरिष्ट पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने अवगत कराया कि खुर्सीपार, कुम्हारी, सिकोलाभाठा एवं अन्य चिन्हित स्थानों पर नशीली पदार्थों के आदतन तस्करों पर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही नारकोटिक्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाहियां भी की जा रही है। तस्करों एवं सार्वजनिक स्थानों पर नशे का सेवन कर व्यवधान करने वालों की सूचना देने हेतु विभाग द्वारा टोल फ्री नं. 1933 जारी की गई है। आम जनता उक्त टोल फ्री नं. पर सूचना दे सकते है। विभाग द्वारा सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। एसएसपी ने ड्रग लाइसेंसी कंपनियॉ एवं ई-कामर्स कंपनियों द्वारा ड्रग की सप्लाई पर चिंता जाहिर करते हुए औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इस पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। औषधि प्रसाधन अधिकारी ने अवगत कराया कि उनकी टीम द्वारा सभी मेडिकल दुकानों की जांच की जा रही है। साथ ही बिक्री किए जा रही मेडिसिन्स की रिकार्ड रखने के निर्देश दिए गए है। वहीं नारकोटिक्स दवाइयों के रिकार्ड में गड़बड़ी मिलने पर मेडिकल दुकानों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों से संबंधित स्पोर्ट्स आफिसरों को खेल मैदान एवं परिसर के आस-पास मादक पदार्थों के बिक्री पर नजर रखने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर सिंह ने जिले में नारकोटिक्स एवं नशा मुक्ति अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने कहा।

शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त, निगम की बड़ी कार्रवाई

भिलाईनगर। जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफकड़ी कार्रवाई की गई। निगम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपेश कुमार नथवानी द्वारा अपने 650 वर्गफीट रजिस्ट्री क्षेत्रफल के अतिरिक्त शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था। इस संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन को जिला नियमितीकरण समिति एवं आयुक्त राजस्व संभाग स्तर पर निरस्त कर दिया गया था। निगम के जोन-2 वैशाली नगर राजस्व विभाग द्वारा संबंधित निर्माणकर्ता को कई बार नोटिस जारी कर रजिस्ट्री क्षेत्र से अतिरिक्त शासकीय भूमि पर किए गए निर्माण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही समय-समय पर निगम को इसकी जानकारी देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद 9 जून 2026, मंगलवार को जोन-2 वैशाली नगर के राजस्व विभाग, बेदखली विभाग तथा पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है।
कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस '

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है । इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में (इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन) द्वारा की गई थी । इसका उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा बच्चों को शिक्षा सुरक्षा और बेहतर भविष्य का अधिकार दिलाना है। बाल श्रम बच्चों की शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। आज भी विश्व के अनेक देशों में लाखों बच्चे आर्थिक मजबूरियों के कारण श्रम करने को विवश है । इस दिवस के माध्यम से सरकारे सामाजिक संगठनों और नागरिकों को बाल श्रम उन्मूलन के लिए मिलकर कार्य करने का संदेश दिया जाता है । विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हमें यह संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षित बचपन उपलब्ध कराया जाए । बाल श्रम मुक्त समाज का निर्माण ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है इसलिए हमें बाल श्रम का विरोध करते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। बचपन का अधिकार, शिक्षा का उपहार - बाल श्रम का करें बहिष्कार।

नीट-2026 परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

दुर्ग। आगामी नीट-2026 परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने शंकराचार्य कॉलेज ऑफनर्सिंग, हुडको भिलाई में परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्यों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिले के 19 परीक्षा केन्द्रों में 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एसओपी का कड़ाई से पालन करते हुए पूरी गंभीरता एवं सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने सभी परीक्षा केन्द्रों में पेयजल, पंखे, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होना चाहिए तथा केन्द्र परिसर में टेंट, एलईडी या अन्य अनावश्यक व्यवस्थाएं नहीं लगाई जाएं। परीक्षार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए सभी केन्द्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत या अव्यवस्था की स्थिति नहीं बननी चाहिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य उपस्थित थे।

कर्बला के शहीदों की याद में मनाया जाएगा मोहर्रम

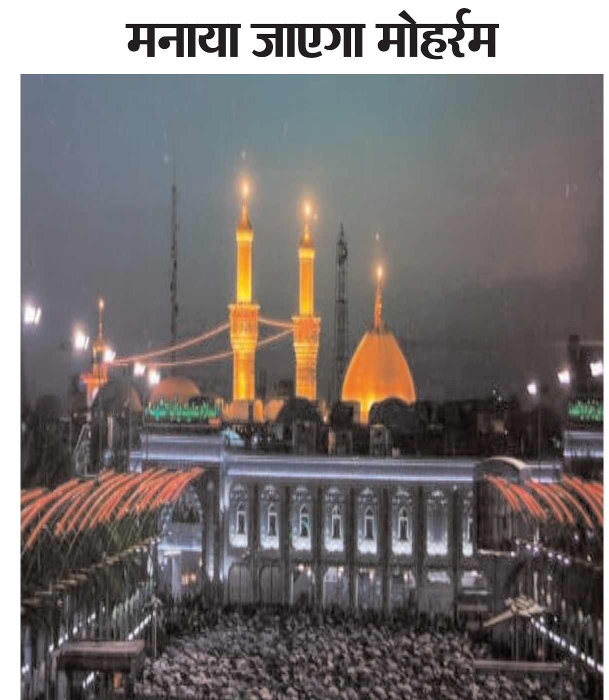

दुर्ग में 10दिवसीय तकरीर (प्रवचन) का आयोजन, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी की तैयारी शुरू

दुर्ग। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लेमीन कमेटी द्वारा 10 दिवसीय मोहर्रम के अवसर पर तकरीर (प्रवचन) का आयोजन किया जा रहा है.जिसमें दस दिनों तक क़र्बला के शहीदों के बारे में जानकारी दी जाएंगी। तकिया पारा ईदगाह मैदान में हर साल की तरह इस साल भी 17जून से 26जून तक 10 दिवसीय तकरीर प्रवचन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। जिसमे मौलाना हासिम कानपुरी 10दिन 1मोहर्रम से 10मोहर्रम तक तकरीर करेंगे. और साथ ही साथ पैगमबर साहब के वंसज पीर सैय्यद जामी अशरफ साहब किछोछा शरीफ (उ प्र) से भी आ रहे है. जो 8मोहर्रम से 10मोहर्रम तक अपना तकरीर (प्रवचन) करेंगे। अंजुमन के जुनैद आज़मी ने जानकारी देते हुए बताया कि, कार्यक्रम का 65वा वर्ष है.इस साल कार्यक्रम 17जून को शाम बाद नमाज़ मगरिब परचम कुशाई (ध्वजारोहण)किया जायेगा. 18जून गुरुवार से 26जून शुक्रवार तक प्रवचन का आयोजन होगा.साथ ही साथ पैगम्बर साहब के वंसज सरकार जामी मिया भी काफ़ी सालो बाद दुर्ग शहर में आ रहे है. जिससे मुस्लिम समाज में हर्ष का माहौल है। कार्यक्रम में दुर्ग एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे । आयोजन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। प्रोग्राम तकिया पारा ईदगाह मैदान मे रात्रि 10 बजे से शुरू हो जायेगा.और साथ ही साथ महिलाओ के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है।

सीसी रोड, नाली और पुलिया निर्माण से नागरिकों को मिलेगी बेहतर सुविधा

वार्ड 38 एवं 39 में सीसी रोड, नाली और पुलिया निर्माण कार्यों की सौगात, महापौर ने किया भूमिपूजन

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में विकास कार्य लगातार जारी हैं। इसी क्रम में आज महापौर अलका बाघमार ने वार्ड क्रमांक 39 एवं वार्ड क्रमांक 38 में विभिन्न निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। वार्ड क्रमांक 39 में डॉ. कौशिक के घर से मुकुंद भवन तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। वहीं वार्ड क्रमांक 38 में पदम पाटनी के निवास से आशीष मारूति के निवास तक, मधुबन वाटिका से खंडेलवाल कॉलोनी तक तथा वार्ड के विभिन्न स्थानों में आर.सी.सी. नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा मिलपारा क्षेत्र में भी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, एमआईसी सदस्य शेखर चन्द्राकर, नीलेश अग्रवाल, पार्षद गुलाब वर्मा, पार्षद रामचंद्र सेन, रंजीता पाटिल, सहायक अभियंता सुरेश केवलानी, उप अभियंता मोहित मरकाम सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य प्रत्येक वार्ड में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में जलभराव और आवागमन संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए नाली, पुलिया और सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी तथा जल निकासी व्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम जनहित से जुड़े विकास कार्यों को निरंतर गति प्रदान कर रहा है और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर ने कहा कि निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा

उन्होंने बताया कि सड़क, नाली और पुलिया जैसे कार्य सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर वार्डों में आवश्यक विकास कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कार्यक्रम के दौरान पार्षदों एवं स्थानीय नागरिकों ने बारिश के पूर्व महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की सौगात मिलने पर महापौर अलका बाघमार एवं नगर निगम प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया तथा क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

स्वत्वाधिकारी , प्रकाशक, एवं मुद्रक ज्वाला प्रसाद अग्रवाल द्वारा असमा पब्लिशर्स प्रा. लि. जयस्तंभ चौक, रायपुर, पिन - 492001 छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं झुलेलाल मंदिर के पीछे, पाटनकर कालोनी, सिंधी कालोनी, दुर्ग पिन- 491001 (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक - ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । e mail - jwalaexpress@gmail.com , मोबाईल- 9993590905, 7000489995